लखनऊ

गुरुवार, 20 अगस्त , 2026

वर्ष : 11 । अंक: 351

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई मोती गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए।

TODAY WEATHER

DAY 32° Hi

NIGHT 28° Low

संक्षेप

नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर बड़ी कार्रवाई, 22 परीक्षाएं रद्द; 2628 अफसरों-कर्मियों की नौकरी खत्म होगी

रांची। झारखंड में नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी और एसआईटी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित 22 परीक्षाएं एक साथ रद्द कर दी हैं। इन फैसलों से 2,628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इनमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा से नियुक्त 342 अधिकारी, 54 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, 63 एसडीपीओ, 237 महिला पर्यवेक्षिका और जेएसएससी-सीजीएल से नियुक्त 1,932 कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी लोग अलग-अलग विभागों में नौकरी कर रहे थे या इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए थे। सरकार ने छह अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित कर दी है, जबकि वर्ष 2014 से लेकर अब तक आयोजित 17 भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने मंगलवार रात 11.45 बजे इससे संबंधित कुल आठ अधिसूचनाएं जारी की हैं। विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचनाओं में बताया गया है कि ये फैसले सीआईडी और एसआईटी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिए गए हैं। सरकार के फैसले के तहत जेएसएससी की विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी जेएसएससी-सीजीएल को रद्द कर दिया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से 1,932 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी।

कांग्रेस का केजरीवाल पर वार: पीएम मोदी जैसा व्यवहार करते हैं, बड़े-बड़े वादों पर चुप्पी

नई दिल्ली, एजेंसी। बुधवार को कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि आप ने पंजाब सरकार की आलोचना करने वाले कई पत्रकारों के फ़ेसबुक पेज हटवाने के लिए कॉपीराइट दावों का इस्तेमाल किया। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उन्हें मोदी जैसा बनने की चाहत रखने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि आलोचना को लेकर केजरीवाल भी वही तरीका अपना रहे हैं, जिसके बारे में कांग्रेस का कहना है कि केंद्र में बीजेपी सरकार भी वैसा ही करती है। X पर एक पोस्ट में खेड़ा ने कहा कि केजरीवाल अच्छे स्कूलों और मोहल्ला क्लीनिक का वादा करते हैं, लेकिन आरोप लगाया कि उन्होंने विचारधारा या लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई है। खेड़ा ने कहा कि वह कल्याणकारी योजनाओं की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद मोदी की तरह व्यवहार करते हैं – या तो पूरी तरह खामोश हो जाते हैं या फिर जांच-पड़ताल से बचने के लिए जान-बूझकर चुप्पी साधे रखते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब में AAP सरकार ने उन पत्रकारों के Facebook पेजों को निशाना बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (बौद्धिक संपदा) से जुड़े दावों का इस्तेमाल किया, जो सरकार की आलोचना करते थे। उन्होंने कहा, 'इसके पीछे क्या तर्क है? यह कि आलोचक 'पत्रकार' नहीं हैं क्योंकि उनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है।

पटना में राजभवन मार्च के दौरान तेजस्वी यादव हिरासत में

छात्र मुद्दों पर राजद का हल्ला बोल

पटना। बुधवार को बिहार में राजनीतिक तनाव तब बढ़ गया जब पटना में राजद के राजभवन मार्च के दौरान पुलिस ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया। यह विरोध प्रदर्शन पिछले महीने सिवान ज़िले में छात्रों के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर AK-47 राइफ़ल के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगने के लिए आयोजित किया गया था। इस घटना ने काफ़ी आक्रोश पैदा किया था और छात्रों से जुड़े मुद्दों को संभालने के सरकार के तरीके की आलोचना को और तेज़ कर दिया था।

जस्वी यादव ने कहा कि सरकार डरी हुई है। हम छात्रों के मुद्दे पर तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम जेल जाने से नहीं डरते... हम हमेशा छात्रों के अधिकारों, बेरोज़गारी को कम करने, पेपर लीक रोकने और परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं और जनता से डरी हुई है... कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती; हर सरकार को एक दिन जाना ही होता है... हमें सबका समर्थन हासिल है।

राजद सांसद मीसा भारती को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि बिहार के छात्र जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन जब तक सिवान के ज़िला मजिस्ट्रेट को सस्पेंड नहीं किया जाता, वे अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे; राजद और बिहार की जनता पीछे नहीं हटेगी... हो सकता है कि सरकार कुछ दिनों में गोली चलाने का भी आदेश दे दे। राजद के सांसदों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी वाले इस मार्च की शुरुआत पार्टी कार्यकर्ताओं के JP गोलंबर पर इकट्ठा होने और फिर राजभवन की ओर बढ़ने के साथ हुई। इस बीच, पैदल मार्च में शामिल राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि देश भर में, और खासकर बिहार में, छात्र और युवा बार-बार हो रहे पेपर लीक और बेरोज़गारी से नाराज़ हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए झा ने कहा कि देश भर में, खासकर बिहार में, छात्र और युवा नाराज़ हैं।

नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में दावा : नीट सिस्टम अब पूरी तरह सुरक्षित

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि NEET-UG परीक्षा कराने का मौजूदा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित और अभेद्य है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फिजिक्स के पेपर का उदाहरण देते हुए कोर्ट को पूरी प्रक्रिया समझाई। मेहता ने बताया कि सबसे पहले, मॉडरेटर के कई ग्रुप मिलकर 500 सवालों का एक बैंक तैयार करते हैं। इस बैंक से, दूसरे मॉडरेटर चार अलग-अलग प्रश्न-पत्र तैयार करते हैं, जिनमें से हर एक में 100 सवाल होते हैं। इसके बाद NTA के DG चार में से दो पेपर चुनते हैं। फिर इन पेपरों को CISF की सुरक्षा और CCTV की निगरानी में प्रिंटिंग के लिए एक सीलबंद बॉक्स में रखा जाता है। इस बॉक्स में एक डिजिटल चाबी होती है और एक्सेस कोड तभी मिल सकता है जब प्रेस का मालिक NTA के DG से संपर्क करे। बॉक्स खुलने के बाद किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं होती और प्रिंटिंग की पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। 3 मई को NEET UG का पेपर लीक होने के कुछ महीनों बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने NEET परीक्षा में सुधारों को संस्थागत रूप देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने NTA को निर्देश दिया कि वह राधाकृष्णन पैनल और नंदन नीलेकणि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दे। बेंच ने मेहता को सिफारिशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सत्येंद्र जैन को फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया, पिछला केस भी फर्जी था, ये भी फर्जी है : केजरीवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के सह प्रभारी और पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन की एक बार फिर झूठे केस में गिरफ्तारी पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। पार्टी इस कार्रवाई को पंजाब में होने वाले चुनाव से जोड़कर भी देख रही है। "आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन को फिर बीजेपी ने झूठे केस में गिरफ्तार करवा दिया। पिछला केस भी फर्जी था और ये केस भी फर्जी साबित होगा। उन्होंने पूछा कि आखिर भाजपा की ये तानाशाही कब तक चलेगी? जिसे मन करता है, उसे झूठे केस लगाकर जेल में डाल देती है। लेकिन अब बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। ये चाहे जितनी तानाशाही कर लें, अब मोदी सरकार का अंत तय है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्येन्द्र जैन को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया है। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी, वह सबको याद है। पिछला केस भी फर्जी था और यह केस भी फर्जी साबित होगा। उन्होंने कहा कि इनका झूठ एक बार फिर देश के सामने आएगा, लेकिन जेल में बिताए उस वक्त और मानसिक प्रताड़ना की भरपाई कौन करेगा? बीजेपी के पाप का घड़ा अब भर चुका है। ये चाहे जितनी तानाशाही कर लें, अब मोदी सरकार का अंत तय है। पूरी आम आदमी पार्टी और देश की जनता सत्येन्द्र जैन के साथ मज़बूती से खड़ी है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब चुनाव से ठीक पहले पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। पहले भी उनको ढाई साल तक फ़ज़ीर् मामले में जेल में रखा और अब फिर एक और फ़ज़ीर् मामला।

टूटे शौचालय, गायब नल और बदहाल दरवाजे

स्कूल की हालत देख भड़के अभिजीत दीपके, कहा- 1960 के दशक जैसे हालात

हिंगोली। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक सरकारी स्कूल 1960 के दशक में फंसा हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि वहां टूटे हुए शौचालय और कक्षा के दरवाजे और शौचालयों में गायब नल पाए। दीपके, जिनके समूह ने पिछले सप्ताह 'स्कूल ठीक करो' (सरकारी स्कूलों में सुधार करो) अभियान शुरू किया था। उन्होंने मंगलवार को अपने गृह जिले के काडोली गांव में स्थित स्कूल का दौरा किया। उन्होंने कहा, 'ऐसा लगा जैसे मैं 1960 के दशक के किसी स्कूल में गया हूं। एक पुराना टिन की छत वाला

शौचालय, टूटे हुए दरवाजे और शौचालयों में नल नहीं थे। इन शौचालयों का क्या करें? संबंधित अधिकारियों ने (स्कूल परिसर के रखरखाव में) अपना कर्तव्य नहीं निभाया। उन्होंने स्थानीय निवासियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, 'ग्रामीण भी गलत हैं क्योंकि वे चुप रहे।' ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता उन्हें परेशान करते हैं। अगर कोई स्कूल की खराब स्थिति के खिलाफ आवाज उठाता है तो उन्हें मुकदमों में फंसा देते हैं।

उन्होंने चेतावनी दी, 'अगर कोई आवाज उठाता है और मामला दर्ज हो जाता है, तो ऐसा एक, दो या तीन लोगों के मामले में हो सकता है। अगर पूरा गांव आवाज उठाएगा, तो मामला कैसे दर्ज होगा? ग्रामीणों को संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी से अगले दस दिनों में स्कूल की मरम्मत शुरू करने के लिए कहना चाहिए, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे।' इससे पहले मंगलवार को, दीपके ने हिंगोली जिले के धेगज गांव में एक सरकारी स्कूल में छात्रों को कथित तौर पर अपनी कक्षा में झाड़ू लगाने के लिए कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी।

कैंपस का लिया जायजा

वह स्कूल का समय समाप्त होने के बाद शाम करीब 7:30 बजे परिसर में गए और कैंपस का जायजा लिया। स्कूल में उनके दौरे और उसके बाद ग्रामीणों के साथ हुई बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

कुर्सी नहीं, तो ट्रेन भी आगे नहीं जाएगी गार्ड की जिद से थमे वैशाली एक्सप्रेस के पहिए, रेलवे महकमे में हड़कंप

आर्यावर्त क्रांति

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला और अजब-गजब मामला सामने आया है। यहां एक छोटी सी मांग पूरी न होने पर एक महत्वपूर्ण और वीआईपी ट्रेन के पहिए अचानक थम गए। नई दिल्ली से ललितग्राम जा रही वैशाली एक्सप्रेस के गार्ड को जब बैठने के लिए सही कुर्सी नहीं मिली, तो वह इस कदर नाराज हुआ कि उसने ट्रेन को आगे ले जाने से ही साफ इनकार कर दिया। गार्ड की इस जिद से रेलवे अधिकारियों के हाथ-पांव फूल गए और स्टेशन पर भारी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। काफी मान-मनौव्वल के बाद जाकर ट्रेन आगे के सफर के लिए रवाना हो सकी। जानकारी के मुताबिक, 18 अगस्त की सुबह नई दिल्ली-ललितग्राम वैशाली एक्सप्रेस (15566) सुबह करीब 9:47 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची थी। यहां से ट्रेन को आगे ले जाने के लिए गार्ड रामाशीष दास को चार्ज लेना था। लेकिन जब वह गार्ड यान (केबिन) में पहुंचे, तो वहां बैठने वाली कुर्सी टूटी हुई थी। यह देखकर रामाशीष दास भड़क गए और उन्होंने टूटी कुर्सी के सहारे या खड़े होकर ड्यूटी करने से मना कर दिया, जिससे पूरी ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रह गई। बताया जा रहा है कि जो गार्ड लखनऊ से गोरखपुर तक की ड्यूटी करके आए थे, उन्होंने अपने टूल बॉक्स पर बैठकर ही जैसे-तैसे सफर पूरा किया था। लेकिन गोरखपुर से बरौनी के लिए जो चार्ज रामाशीष दास ले रहे थे, उनके पास टूल बॉक्स की जगह ट्रॉली बैग था, जिस पर बैठना मुमकिन नहीं था।

रहमान के भारत दौरे को यादगार बनाना चाहते हैं पीएम मोदी, अधिकारियों को दिया गया निर्देश

नई दिल्ली। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में हालिया तनाव के बावजूद नई दिल्ली संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है। भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का प्रस्तावित भारत दौरा यादगार हो। भारत ने आपसी भरोसे, व्यापार, निवेश और युवाओं के लिए अवसरों को द्विपक्षीय संबंधों का आधार बनाने पर जोर दिया है। हालांकि, शेख हसीना के प्रत्यर्पण और उनके भारत से दिए गए हालिया मीडिया संदेश को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद अब भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

राजदूत की ये बातें मंगलवार को ऐसे समय में सामने आईं, जब 12-13 सितंबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में रहमान के प्रस्तावित दौरे को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। यह अनिश्चितता ढाका की ओर से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच पैदा हुई नई तल्खी के कारण है।

द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, त्रिवेदी ने मंगलवार को भारतीय उच्चायोग की ओर से बांग्लादेश के प्रमुख कारोबारी नेताओं और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के प्रतिनिधिमंडल के लिए आयोजित एक स्वागत समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संदेश था कि दोनों नेताओं को मुलाकात करनी चाहिए। बैठक के दौरान राजदूत त्रिवेदी ने भरोसा दिलाया कि भारत दौरे के दौरान पीएम रहमान का उचित और सम्मानजनक स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बस एक बात कही। हमें मिलना चाहिए।

कोलकाता के होटल में भीषण आग : बच्चे समेत 9 लोगों की मौत, छह लोग अस्पताल में भर्ती

कोलकाता, एजेंसी। कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके की फ्री स्कूल स्ट्रीट स्थित होटल में मंगलवार-बुधवार की मध्यरात्रि भीषण आग लगने से एक बच्चे समेत नौ लोगों की मौत हो गई। हादसे में छह अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर दमकल की चार गाड़ियों और आपदा प्रबंधन टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान चलाया और आग पर काबू पाया।

अग्निशमन विभाग के मुताबिक, आग रात में करीब दो बजे मिर्जा गालिब स्ट्रीट के पास स्थित होटल में लगी। शुरुआती जानकारी के अनुसार, होटल से सबसे पहले धुआं निकलता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि आग होटल से बाहर निकलने वाले रास्ते के आसपास फैल गई थी। आधी रात के समय आग लगने के कारण होटल में ठहरे कई लोगों को घटना की जानकारी देर से हुई।

धुएं के कारण कई लोग होटल के अंदर फंस गए। दमकलकर्मियों ने राहत अभियान चलाकर लोगों को बाहर निकाला। नौ लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। रिपोर्टों के अनुसार, मृतकों में बांग्लादेशी नागरिक भी थे, जो इलाज के लिए कोलकाता आए हुए थे।

जनगणना के सवालों पर भड़की कांग्रेस? : जाति से लेकर जन्मस्थान तक के सवालों पर घमासान, सरकार पर हुई हमलावर

सवाल पूछने का तरीका जानबूझकर गलत: जयराम

रमेश ने अपनी पोस्ट में कहा, 'जनगणना 2027 में जाति के बारे में सवाल पूछने का तरीका जानबूझकर गलत है। धर्म, जन्म तिथि और माता-पिता के जन्म स्थान के बारे में इतने बारीक सवाल पहले कभी नहीं पूछे गए।' उन्होंने आगे कहा कि जनगणना गोपनीय होती है। साफ है कि जनगणना 2027 के पीछे कोई गहरा और बुरा मकसद है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने जनगणना 2027 में जाति, धर्म और माता-पिता से जुड़ी जानकारी जुटाने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि जाति संबंधी सवालों की संरचना जानबूझकर गलत रखी गई है और जनगणना के पीछे 'गहरा और बुरा मकसद' हो सकता है। कांग्रेस ने खास तौर पर 2021 के सुप्रीम कोर्ट हलफनामे का हवाला देते हुए पूछा है कि जब सरकार ने जातियों की पहचान के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू की उपयोगिता बताई थी, तो 2027 की जनगणना में इसे शामिल क्यों नहीं किया गया। कांग्रेस ने मंगलवार को भी आरोप लगाया था कि मोदी सरकार जाति जनगणना को रोकना चाहती है। पार्टी ने सवाल उठाया था कि जनगणना 2027 में जाति चुनने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू क्यों शामिल नहीं किया गया, जबकि केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में इसकी सिफारिश की थी। विपक्षी पार्टी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल 2025 को जाति जनगणना कराने की घोषणा कर 'पूरी तरह से यू-टर्न' लिया था। कांग्रेस का कहना है कि अब सरकार 'अपने ही पहले वाले यू-टर्न पर यू-टर्न' ले रही है। जयराम रमेश ने बताया कि 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था। इसमें जाति जनगणना की मांग को स्पष्ट रूप से खारिज किया गया था। हालांकि, रमेश ने एक्स पर साझा की गई अपनी पोस्ट में हलफनामे के पैरा 12 (d) का हवाला देते हुए कहा कि इसमें जातियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए ड्रॉप-डाउन मेनू का सुझाव दिया गया था। रमेश ने हलफनामे के संबंधित हिस्से को उद्धृत करते हुए कहा कि 2011 की जनगणना से पहले जातियों का कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था।

तमिलनाडु में सीएम विजय के दो बड़े ऐलान, हेल्थ बीमा कवर 5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख

दूध खरीद मूल्य में भी 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य के लोगों और दूध उत्पादकों के लिए दो बड़े फैसलों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा की। इसके साथ ही सरकारी डेयरी कंपनी आविन के लिए दूध खरीद मूल्य 38 रुपये से बढ़ाकर 41 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी व्यक्ति के लिए महज सुविधा नहीं, बल्कि उसका मूल अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की आय और उनके रहने के स्थान की परवाह किए बिना सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की ओर से कई नई पहल भी शुरू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने सरकारी डेयरी कंपनी आविन की ओर से किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमत में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब दूध उत्पादकों को 38 रुपये के बजाय 41 रुपये प्रति लीटर का भुगतान किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार की ओर से 3 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि भी शामिल होगी।

संक्षेप

टूटे बिजली तार में दौड़ रहा करंट, बड़े हादसे का खतरा

बल्दीराय/सुल्तानपुर। तहसील क्षेत्र के धनपतगंज फीडर अंतर्गत ग्रामसभा पड़रे के बहेरी गांव में बिजली विभाग की लापरवाही ग्रामीणों के लिए कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। सोमवार की रात 17 अगस्त को बारिश के दौरान खम्भे की टूटी केबल अचानक धू-धू कर जलने लगी। तार में करंट दौड़ने से आसपास रहने वाले ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई और कई घरों के लोगों को करंट उतरने का भय सताने लगा। ग्रामीणों के मुताबिक, खम्भे की केबल टूटने के बाद भी उसमें विद्युत प्रवाह बना हुआ है। बारिश के मौसम में जमीन और आसपास के हिस्सों में नमी होने के कारण स्थिति और अधिक खतरनाक बनी हुई है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग को इसकी सूचना भी दी, लेकिन आरोप है कि अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते टूटी केबल को दुरुस्त नहीं कराया गया तो किसी भी समय बड़ी अनहोनी हो सकती है। खासकर आसपास के घरों में रहने वाले लोगों, बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरशद अली, इंद्रजीत यादव सहित कई ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित विद्युत अधिकारियों को निर्देशित करने तथा खम्भे से टूटी केबल को शीघ्र जुड़वाने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने जल्द कार्रवाई नहीं की और कोई हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। अब देखना यह है कि विद्युत विभाग इस गंभीर समस्या पर कब तक कार्रवाई करता है।

21 अगस्त को होगी कृषि यंत्रों की ई-लॉटरी, किसानों से शामिल होने की अपील

सुलतानपुर। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों की बुकिंग कराने वाले किसानों के चयन के लिए 21 अगस्त 2026 को जिला स्तरीय ई-लॉटरी आयोजित की जाएगी। ई-लॉटरी सुबह 10 बजे विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में होगी। उप कृषि निदेशक, सुलतानपुर की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार वर्ष 2026-27 में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत 16 जुलाई से 10 अगस्त तक किसानों ने विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की थी। लक्ष्य से अधिक बुकिंग वाले कृषि यंत्रों के लिए ई-लॉटरी के माध्यम से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा। ई-लॉटरी में रोटावेटर, पावर ऑपरेटेड चौप कटर, कंबाइन हार्वेस्टर, हैरो, कल्टीवेटर, स्ट्रॉ रीपर, किसान ड्रोन, कस्टम हायरिंग सेंटर, फार्म मशीनरी बैंक, सुपर सीडर, बेलिंग मशीन, स्ट्रॉ बॉलर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, मिनी दाल मिल, मिनी राइस मिल, ऑयल मिल, पावर टिलर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, शुगरकेन पावर बीडर समेत अन्य कृषि यंत्र शामिल हैं। विभाग के अनुसार ई-लॉटरी प्रक्रिया एएलसीडी के माध्यम से उपस्थित समिति एवं किसानों के समक्ष पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। उप कृषि निदेशक ने अधिक से अधिक किसान भाइयों से ई-लॉटरी की प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अपील की है।

22 अगस्त को अमहट में अलविदाई जुलूस का आयोजन

सुल्तानपुर। 8 रबीउल अव्वल दो माह आठ दिन का अलविदाई जुलूस अय्यामे अजा का आखिरी दिन का आयोजन किया गया है। जिसमें 22 अगस्त दिन शनिवार को मोमनीन गोराबारिक अमहट की तरफ से सुबह 7बजे जामा मस्जिद गोराबरिक अमहट में एक मजलिस होगी जिसको मौलाना मोहम्मद जाफर खान पढ़ेंगे। इसके बाद शबीह ताबूत हजरत इमाम हसन असकरी अलैहिस्सलाम व हुसैन के घरवालों के कर्बला से मदीना वापसी के सिलसिले में अमारी का जुलूस उठकर हुसैनिया नजर अली शाह हुसैनिया नौ तामीर हुसैनिया शेख खानी हुसैनिया बादल खां होकर हुसैनिया नौतामीर के सामने शाम 7 बजे समाप्त होगा जिसमें मौलाना मुशीर अब्बास खान मौलाना सैयद सिबतैन अब्बास रिजवी मौलाना सैयद आमिर काजिमी तकरीर करेंगे। और सुल्तानपुर की मुकामी अंजुमनो के अलावा बाहरी अंजुमने अंजुमन फरोगे अजा बाराबंकी अंजुमने गुलशन ए इस्लाम भौंरा सादातभी नौहा ख्वानी और मातम करें गी औरअंत में हुसैनी काफ़ले के मदीना वापसी पर रौंजा ए रसूल व जन्नतुल बकीय का मंजर पेश किया जाएगा यह जानकारी हैदर अब्बास खान अध्यक्ष हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर ने दी है।

रिटायर्ड शिक्षक को डिजिटल अरेस्ट कर सात लाख की ठगी, आतंकियों से बताया था कनेक्शन

मेरठ। पुलिस-प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर जिले के नागरिकों को लगातार डिजिटल अरेस्टिंग और साइबर क्राइम के नाम पर ठगी के मामलों से सचेत किया जा रहा है। मगर, इसके बावजूद कई लोग दहशत में आकर अपनी गाढ़ी कमाई ठगों के हाथों गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नौचंदी थाना क्षेत्र से सामने आया है। जहां साइबर ठगों ने आतंकियों से कनेक्शन बताकर नौचंदी क्षेत्र निवासी एक रिटायर्ड शिक्षक को लगभग एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट रखा।
इस दौरान ठगों ने रिटायर्ड शिक्षक और आतंकियों के बीच कनेक्शन बताकर जेल भेजने का डर दिखा रिटायर्ड शिक्षक से सात लाख की रकम ठग ली। ठगी का एहसास होने पर रिटायर्ड शिक्षक ने ठगों को और रकम देने से इनकार कर दिया। इसके बाद साइबर क्राइम थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिसके बाद पुलिस मामले की जांच और कार्यवाही में जुटी है।
दरअसल, नौचंदी थाना क्षेत्र की फूलबाग कॉलोनी के रहने वाले जीत सिंह एक सरकारी कॉलेज से रिटायर्ड शिक्षक हैं। जीत सिंह के मुताबिक बीती नौ अगस्त को उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात शख्स की कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम रणजीत सिंह बताते हुए खुद को एनआईए का अधिकारी बताया। रणजीत ने जीत सिंह से कहा कि वह आतंकवादियों से मिले हुए हैं। उनके बैंक खाते में आतंकियों के आईसीआईसीआई बैंक के खाते से दो करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई है। साथ ही जीत सिंह के विरुद्ध वारंट जारी करने की धमकी देते हुए जीत सिंह की बात अपने अफसर से कराई। रिटायर्ड शिक्षक जीत सिंह का आरोप है कि इसके बाद लगातार संदीप ग्रोवर और खुद को एनआईए का चीफ बताने वाला राकेश अग्रवाल फोन पर उनके संपर्क में रहे। जीत सिंह को जेल भेजने का डर दिखाते हुए आरोपियों ने उनकी दो एफडी तुड़वाकर सेंट्रल बैंक के खाते से सात लाख की रकम कृष्णा नाम के व्यक्ति के महिंद्रा बैंक के खाते में ट्रांसफर करवाई।

सुल्तानपुर की बेटी ने जीता सिल्वर मेडल

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। न्यू एंजेल्स सर स्कूल प्रतापगढ़ में 15 से 18 अगस्त तक आयोजित सीबीएसई बोर्ड बॉक्सिंग चौंपियनशिप में सुल्तानपुर जनपद की गोल्डन बेल्स ग्लोबल स्कूल, बरौसा की छात्रा जाह्नवी शुक्ला ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। जाह्नवी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर नेशनल गेम्स के लिए अपनी जगह बनाई और पूरे सुल्तानपुर जनपद का नाम रोशन किया। सुल्तानपुर जनपद से कुल 7 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, जिसमें गोल्डन बेल्स ग्लोबल स्कूल के 6 खिलाड़ी एवं टाइनी टॉट्स पब्लिक स्कूल की 1 खिलाड़ी शामिल रहीं। गोल्डन बेल्स ग्लोबल स्कूल की आशी मिश्रा, एंजेल वर्मा, आर्या शुक्ला, अदिति पाण्डेय एवं यशप्रीत जोवेल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। वहीं टाइनी टॉट्स पब्लिक स्कूल की दीप्ति सिंह ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस शानदार उपलब्धि पर गोल्डन बेल्स ग्लोबल स्कूल के बॉक्सिंग कोच मिस्टर शुभम धुरिया, सुल्तानपुर खेल एवं शिक्षा परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, कोषाध्यक्ष रेखा देवी, बॉक्सिंग कोच विजय यादव, स्कूल की प्रिंसिपल रेनू शुक्ला एवं डायरेक्टर राजेश शुक्ला ने सभी खिलाड़ियों एवं कोच को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। गोल्डन किड्स स्कूल, जयसिंहपुर की आभा मिश्रा ने भी खिलाड़ियों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह मेडल सिर्फ जाह्नवी की जीत नहीं, बल्कि पूरे सुल्तानपुर की जीत है। खिलाड़ियों की मेहनत, लगन और लगातार संघर्ष से जिले का नाम लगातार रोशन हो रहा है।

आजमगढ़ में जेन अल्फा हो गए आंदोलति, 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर कहा -

'विज्ञान और गणति के वर्षों से नहीं हैं शिक्षक'

आर्यावर्त संवाददाता

आजमगढ़। आंदोलन की आंच से अब आजमगढ़ भी अछूता नहीं है। यहां पर 26 साल से वज्ञिान और नौ साल से गणति के शक्षिक नहीं होने से जेन अल्फा के वद्यिार्थी शक्षिकों की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बच्चों के आंदोलन की जानकारी के बाद प्रशासन के भी होश उड़ गए और आनन फानन उनको समझाने बुझाने का प्रयास शुरू हुआ तो 48 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दयिा है।

स्मिथ इंटर कालेज अजमतगढ़ में अध्यापकों की कमी से नाराज छात्र-छात्राओं का आक्रोश फूट पड़ा, मंगलवार को विद्यार्थियों ने विद्यालय गेट पर धरना-प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में 26 साल से रसायन विज्ञान व भौतिकी और नौ साल से गणित के प्रवक्ता नहीं हैं। इसके बावजूद छात्रों से फीस वसूली जा रही है। प्रधानाचार्य के 48 घंटे में अध्यापकों की व्यवस्था करने के आश्वासन पर करीब एक घंटे बाद छात्रों ने धरना समाप्त किया। प्रबंधक के मौके पर नहीं पहुंचने से छात्रों ने जमकर नाराजगी व्यक्त की। मंगलवार को विद्यालय खुलते ही सुबह आठ बजे छात्र-छात्राएं गेट पर एकत्र होकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर जीयनपुर पुलिस पहुंची और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। छात्रों ने कहा कि अध्यापक नहीं आए तो 48 घंटे बाद फिर धरना दिया जाएगा। उनका आरोप है कि विद्यालय में 1100 से अधिक छात्र हैं और नामांकन भी जारी है। अध्यापकों की कमी के बावजूद उनसे निजी शिक्षकों के पढ़ाने के नाम पर 50-50 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी लिया जा रहा है। छात्रों ने तत्काल रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित के अध्यापकों की नियुक्ति की मांग की।

भाजपा में रेखा वर्मा का कद बरकरार, बरेली के राजेश अग्रवाल पदमुक्त

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। भाजपा की नई टीम में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता राजेश अग्रवाल को जगह नहीं मिली है। राजेश अग्रवाल के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद से हटने के बाद बरेली के राजनीतिक हलकों में बस एक ही सवाल है कि भाजपा अब उन्हें कौन सा नया पद या जिम्मेदारी सौंपेगी। हालांकि, पार्टी की तरफ से उनके नए काम को लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। वहीं, लखीमपुर खीरी के धौरहरा की पूर्व सांसद रेखा वर्मा को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखने के लिए पिछड़ा वर्ग को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।

राजेश अग्रवाल छह बार विधायक और प्रदेश के वित्त मंत्री रह चुके हैं। नए अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में उन्हें इस पद से मुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को अतिरिक्त रूप से दी गई है। पार्टी इस कमी को दूर करने के लिए जल्द ही कोई निर्णय ले सकती है। चर्चा है कि कैंट विधायक संजीव अग्रवाल को प्रदेश कोषाध्यक्ष पद पर प्रोन्नत किया जा सकता है। प्रदेश भाजपा की नई टीम में कोषाध्यक्ष का पद अभी खाली है। फिलहाल, संजीव अग्रवाल प्रदेश में सहकोषाध्यक्ष हैं।

बढ़ती उम्र मानी जा रही वजह

राजेश अग्रवाल कुछ ही दिनों में 83 साल के होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि बढ़ती उम्र के कारण उनसे यह अहम जिम्मेदारी वापस ली गई है। उनके बेटे मनीष अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं और नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि है। उधर, रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए रखना पिछड़ा वर्ग को अपने साथ बनाए रखने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। पार्टी विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है।

पीडीए की काट को पिछड़ा वर्ग पर मेहरबानी

सपा के पीडीए फार्मूले की काट को भी भाजपा मेहनत कर रही है। रुहेलखंड से सटी धौरहरा सीट की पूर्व सांसद रेखा वर्मा को लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है। इसकी वजह रेखा वर्मा का कुर्मी बिरादरी से होना बताया जा रहा है, जो पिछड़ा वर्ग में भाजपा के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। इसी तरह पिछले दिनों ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष के रूप में लोधे समाज से जुड़े पूरनलाल लोधी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी।

सीएचसी अधीक्षक पर लोहे की रॉड से हमला, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

आर्यावर्त संवाददाता

अखण्डनगर/सुल्तानपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अखण्डनगर में बुधवार सुबह ड्यूटी पर तैनात अधीक्षक डॉ. सत्येंद्र सिंह पर एक युवक ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटना करीब 10.45 बजे अधीक्षक के कक्ष में हुई। हमले में डॉ. सिंह घायल हो गए। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, ग्राम सभा प्राणनाथ पुरबछेणिया निवासी सचिन गौड़ हाथ में लोहे की रॉड लेकर अधीक्षक के कक्ष में पहुंचा और डॉ. सिंह पर हमला कर दिया। शोर सुनकर अस्पताल के कर्मचारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लाइन में खड़े होने को लेकर हुए विवाद के कारण उसने हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक अमित सिंह पुलिस बल के साथ सीएचसी पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लेकर अखण्डनगर थाने ले गए। वहीं, हमले से नाराज डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर ओपीडी और आपातकालीन सेवाएं बंद कर विरोध जताया तथा थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीओ कादीपुर विनय गौतम ने बताया कि सरकारी कार्य कर रहे सीएचसी अधीक्षक पर युवक ने हमला किया, जिससे वह घायल हुए हैं। डॉ. सिंह की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कर्तव्यनिष्ठा और देशसेवा ने बढ़ाया बल्दीराय का गौरव, राजेश बने कैप्टन

आर्यावर्त संवाददाता

बल्दीराय/सुलतानपुर। भारतीय सेना की वर्दी पहनकर देश की सीमाओं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समर्पित सेवा करने वाले बल्दीराय क्षेत्र के लाल राजेश कुमार पांडे ने अपनी मेहनत, अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा से क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। तहसील बल्दीराय क्षेत्र के पूरे पंडित आचार्य निवासी राजेश कुमार पांडे को भारतीय सेना में उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा के लिए कैप्टन पद से सम्मानित किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही पूरे क्षेत्र में हर्ष और गर्व का माहौल है। राजेश कुमार पांडे वर्तमान में 165 फील्ड रेजीमेंट, अहमदाबाद (गुजरात) में तैनात हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनकी सैन्य सेवा, समर्पण और उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उन्हें कैप्टन पद से विभूषित किया गया। यह सम्मान उनके लिए केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उस परिवार और क्षेत्र के लिए भी गौरव का विषय है, जहां से निकलकर उन्होंने राष्ट्रसेवा को अपना दायित्व बनाया। राजेश की पदोन्नति की खबर मिलते ही परिजनों, रिश्तेदारों और क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि देश की रक्षा और सेवा से बड़ा कोई गौरव नहीं होता। राजेश कुमार पांडे ने अपने परिश्रम और कर्तव्य के प्रति समर्पण से यह साबित किया है कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी युवा अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर राष्ट्रसेवा के सर्वोच्च दायित्वों तक पहुंच सकते हैं। परिजनों ने कहा कि राजेश की उपलब्धि परिवार के लिए गर्व का क्षण है। उनकी सैन्य यात्रा क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। लोगों का कहना है कि तिरंगे की शान के लिए समर्पित सैनिकों की उपलब्धियां पूरे समाज की उपलब्धियां होती हैं।

फिर अयोध्या लौटे गोपाल राव, राम मंदिर में किए दर्शन, चंपत राय से मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले के बीच एक बार फिर गोपाल राव के अयोध्या पहुंचने से चर्चाएं तेज हो गई हैं। बुधवार को अयोध्या पहुंचे गोपाल राव ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी मुलाकात की। दोनों के बीच हुई मुलाकात को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

बताया जाता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद गोपाल राव 15 जुलाई को अयोध्या से बाहर चले गए थे। इसके बाद संघ स्तर से भी उनके दायित्व और केंद्र को लेकर बदलाव किए जाने की चर्चा सामने आई थी। संघ ने उनका केंद्र अयोध्या से बदल दिया है। ऐसे में करीब एक माह बाद उनका अयोध्या लौटना और राम मंदिर में दर्शन के साथ चंपत राय से मुलाकात करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

चढ़ावा चोरी प्रकरण के बाद बदले घटनाक्रम के बीच उनकी अयोध्या वापसी को लेकर मंदिर और संघ से जुड़े लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने और रिपोर्ट ट्रस्ट को उपलब्ध कराए जाने के बाद मंदिर व्यवस्था से जुड़े कई लोगों की भूमिका को लेकर भी चर्चा चल रही है। ऐसे में गोपाल राव की वापसी को इस पूरे घटनाक्रम से जोड़कर देखा जा रहा है।

चढ़ावा चोरी जांच के बीच राम मंदिर व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अनिल मिश्रा के 2 करीबी हटाए गए, एंट्री पर भी लगी रोक

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

अयोध्या। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी मामले की जांच चल रही है। गृह विभाग की ओर से जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की अंतिम रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाओं में एक और बड़ा बदलाव किया गया है। पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा के 2 करीबियों को मंदिर की व्यवस्था से हटा दिया गया और उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है।

मंदिर की व्यवस्था से जिन 2 लोगों दूर किया गया हैं, वो हैं केडी तिवारी उर्फ बड़े बाबू और बजरंग पाठक पर कार्रवाई। केडी तिवारी रामलला के आभूषणों और श्रद्धालुओं की ओर से समर्पित मूल्यवान वस्तुओं के हिसाब-किताब की जिम्मेदारी संभालते थे तो बजरंग पाठक वीआईपी दर्शनार्थियों के लिए प्रसाद, अंगवस्त्र और अन्य भेंट की व्यवस्था देखते थे।

बिजैसी स्थित तीर्थ क्षेत्र पुरम भेजे गए

दोनों को पहले शिकायत के आधार पर नोटिस दिया गया, इसके बाद राम मंदिर की व्यवस्था से हटाकर बाग बिजैसी स्थित तीर्थ क्षेत्र पुरम भेज दिया गया। ट्रस्ट की ओर से कार्रवाई के बाद दोनों के राम मंदिर परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। दोनों ही मंगलवार से मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं।

महिला CO के बीच विवाद के बाद कार्रवाई

बताया जा रहा है कि राम मंदिर में तैनात महिला क्षेत्राधिकारी की शिकायत के बाद कार्रवाई हुई। दर्शन के दौरान प्रसाद की व्यवस्था को लेकर बजरंग पाठक और महिला CO के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद शिकायत की गई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के बाद लगातार बदल रही व्यवस्थाओं के बीच यह कार्रवाई अहम मानी जा रही है।

साधु-संतों से मिल रहे चंपत राय

इस बीच खबर है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने और उसे श्री ट्रस्ट के साथ साझा किए जाने की पुष्टि के बीच ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा लगातार साधु-संतों से मुलाकात कर रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि रिपोर्ट ट्रस्ट के साथ साझा की गई है लेकिन उसमें क्या लिखा, इसकी जानकारी नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के नाम शामिल नहीं थे।

SC के निर्देश के बाद जांच कर रही SIT

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी पूरे केस की अलग से जांच कर रही है और उसे अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल करनी है। सूत्रों का कहना है कि संतों के एक समूह ने खुले तौर पर चंपत राय का समर्थन करना शुरू कर दिया है तो पूर्व ट्रस्टी मिश्रा अलग-अलग जगहों पर छोटी-छोटी बैठकें कर अपने और राय पर लगे सभी आरोपों को साजिश बताकर खारिज कर रहे हैं। कई साधुओं और संतों का भी मानना है कि चंपत राय निर्दोष हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला इस साल जून के पहले हफ्ते में सामने आया था, लेकिन इस मामले में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने पर जोर, सीडीओ ने अधिकारियों को दिए निर्देश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। जिले में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को प्रेरणा सभागार में जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में खेल योजनाओं की समीक्षा के साथ विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं अनुमोदन किया गया।बैठक में समिति के खाते में वर्तमान में उपलब्ध करीब 36 लाख 24 हजार 790 रुपये की धनराशि तथा उसके सदुपयोग को लेकर भी चर्चा हुई। एजेंडे में जिले में जिम एवं तरणताल संचालकों से वार्षिक पंजीकरण व अन्य शुल्क के रूप में 15 हजार रुपये एकमुश्त लिए जाने, नए लाइसेंस/राइफल क्लब एवं नवीन हथियार लेने वालों से पांच हजार रुपये प्रोत्साहन समिति में जमा कराने सहित विभिन्न प्रस्ताव शामिल रहे। शराब व बीयर के नए लाइसेंस जारी होने पर प्रत्येक लाइसेंसधारक से पांच हजार रुपये समिति में जमा कराने तथा भारी वाहन पंजीकरण शुल्क से एक हिस्सा समिति में जमा कराने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। बैठक में ईंट-भट्ठा मालिकों से प्रतिवर्ष पांच हजार रुपये लिए जाने, उद्यमियों एवं खिलाड़ियों को खेल प्रशिक्षण संबंधी सामग्रीध्उपकरण उपलब्ध कराने तथा स्टेडियम परिसर में महिला चेंजिंग रूम और शौचालय निर्माण कराने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रमों के लिए 50 प्लास्टिक कुर्सियों की खरीद का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल रहा।सीडीओ विनय कुमार सिंह ने खेल से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

'जापान लैंड ऑफ राइजिंग सन, यूपी लैंड ऑफ सूर्यवंश', यूपी - जापान इन्वेस्टमेंट मीट में योगी का बड़ा संदेश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। यूपी -जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान और उत्तर प्रदेश के बीच आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोनों क्षेत्रों के रिश्ते केवल निवेश और कारोबार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहरी सांस्कृतिक और सभ्यतागत समानताएं भी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान को 'लैंड ऑफ राइजिंग सन' कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश 'लैंड ऑफ सूर्यवंश' है। उन्होंने यूपी को 'लैंड ऑफ श्रीराम', 'लैंड ऑफ श्रीकृष्ण', 'लैंड ऑफ बुद्ध' और 'लैंड ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल' भी बताया।

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता का जिक्र करते हुए राज्य को भारत का 'फूड बास्केट' बताया। उन्होंने कहा कि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत है। उन्होंने जापानी कंपनियों को कृषि, खाद्य प्रसंस्करण और इससे जुड़े क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं की ओर भी आकर्षित किया।

बौद्ध विरासत और काला नमक चावल का जिक्र

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की बौद्ध विरासत का उल्लेख करते हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे प्रमुख स्थलों को राज्य की वैश्विक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने भगवान बुद्ध से जुड़े काला नमक चावल का भी जिक्र किया और बताया कि इसे उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना में शामिल किया गया है।

टॉप थ्री इकोनॉमी में यूपी का दावा

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सरकार की स्पष्ट नीतियों के चलते उत्तर प्रदेश भारत की टॉप थ्री इकोनॉमी में शामिल होते हुए देश के ग्रोथ इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले नौ वर्षों में सुरक्षा और स्थायित्व के साथ राज्य की प्रति व्यक्ति आय तीन गुना करने में सफलता मिली है। साथ ही यूपी 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

96 लाख MSMEs और 22 हजार से ज्यादा स्टार्टअप

मुख्यमंत्री ने निवेशकों के सामने प्रदेश के औद्योगिक इकोसिस्टम की तस्वीर भी रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में:

96 लाख से अधिक MSMEs
35,000 से अधिक बड़े उद्योग
22,000 से अधिक स्टार्टअप

75,000 एकड़ से ज्यादा डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है।

सीएम योगी ने कहा कि यूपी निवेश और नवाचार के नए केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के मोबाइल उत्पादन का 55 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग यूपी में हो रहा है।

एस्कॉर्ट कुबोटा परियोजना से 4 हजार रोजगार की संभावना

जापानी निवेश का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की एस्कॉर्ट कुबोटा परियोजना का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से लगभग 4,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है। परियोजना के पहले चरण में हर साल 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है।

जापान की क्वालिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तारीफ

सीएम योगी ने कहा कि जापानी उद्योग की सबसे बड़ी ताकत गुणवत्ता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का उद्देश्य राज्य में एक मजबूत और दीर्घकालिक जापानी औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना है।

उन्होंने कहा कि भारत-जापान के रणनीतिक विजन को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में बदलने का यह सही समय है।

मुख्यमंत्री ने जापानी निवेशकों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यूपी सरकार एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में उनके साथ खड़ी है।

फरवरी में जापान दौरे के बाद बढ़ी साझेदारी

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2026 में जापान का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने जापानी उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की थी। जापान और यूपी के संबंधों को लेकर मुख्यमंत्री ने उस दौरान सूर्य की पहली किरण और सूर्यवंश की धरती उत्तर प्रदेश के बीच एक सांस्कृतिक जुड़ाव का उल्लेख किया था।

पुरानी रंजिश में चाकू से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार, दो दिन पहले हुआ था विवाद

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। पुरानी रंजिश को लेकर रास्ते में गाड़ी रोककर चाकू से हमला करने के मामले में थाना बिजनौर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी और उसके मित्र पर चाकू से हमला किया था। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।पुलिस के अनुसार 18 अगस्त 2026 को आशीष चौधरी, पुत्र दुखहरण चौधरी, निवासी न्यू बेहसा, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ अपने मित्र श्वेत मिश्रा, पुत्र नागेंद्र मिश्रा, निवासी गड़ौरा, थाना बिजनौर तथा हासिम अली, पुत्र छुन्नू लाल, निवासी बदाली खेड़ा, कानपुर रोड के साथ थाना बिजनौर पहुंचे। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर तुलसीराम पुत्र महेश कुमार, आयुष पुत्र अज्ञात और एक अज्ञात व्यक्ति ने बीच रास्ते में उनकी गाड़ी रोककर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया। हमले में आशीष चौधरी और उनके मित्र श्वेत मिश्रा को चोटें आईं।तहरीर के अनुसार बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर थाना बिजनौर में मुकदमा संख्या 221/2026, धारा 126(1), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 118(1) बीएनएस तथा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी तुलसीराम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले गाड़ी पीछे करने को लेकर उसका आशीष से विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते उसने 18 अगस्त की शाम अपने साथियों के साथ मिलकर आशीष पर चाकू से हमला किया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।गिरफ्तार आरोपी की पहचान तुलसीराम पुत्र महेश कुमार, निवासी न्यू बेहसा, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ, उम्र करीब 21 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के आपराधिक इतिहास में थाना बिजनौर में दर्ज वर्तमान मुकदमे के अलावा थाना सट्टी, जनपद कानपुर देहात में मुकदमा संख्या 46/2025, धारा 115(2), 333, 351(3), 352 बीएनएस का मामला भी दर्ज है।पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कांस्टेबल अमित कुमार और महिला कांस्टेबल कल्पना गौतम, थाना बिजनौर शामिल रहे।

यूपीएसएसएससी जेई भर्ती पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिले छात्र

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4,612 जूनियर इंजीनियर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार और नाराजगी अब सड़क तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में छात्र लखनऊ की राजभवन कॉलोनी स्थित उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर पहुंचे और भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। छात्रों ने खास तौर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के परिणाम जल्द जारी करने और 'डिपार्टमेंट स्किप' का विकल्प उपलब्ध कराने की मांग रखी। छात्र प्रतिनिधियों ने मुलाकात के दौरान भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी और लंबित चरणों को लेकर अपनी समस्याएं सामने रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि चयन प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाया जाए, ताकि लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को आगे की स्थिति स्पष्ट हो सके। बताया गया कि उपमुख्यमंत्री ने छात्रों की बातें सुनीं और उनकी मांगों पर उचित स्तर पर विचार किए जाने का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि संबंधित विभाग जल्द उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय ले सकता है। इसी दौरान फार्मासिस्ट एलोपैथिक भर्ती के अभ्यर्थी भी अपनी मांग लेकर उपमुख्यमंत्री के आवास पहुंचे। अभ्यर्थियों ने फार्मासिस्ट की सीटें बढ़ाने की मांग रखी। अभ्यर्थियों के मुताबिक, वर्तमान में 564 सीटों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। वहीं, RTI के माध्यम से फरवरी 2025 तक 804 पद खाली होने की जानकारी मिलने का दावा किया गया है। अभ्यर्थियों ने खाली पदों के सापेक्ष भर्ती में सीटें बढ़ाने की मांग की।

छात्रों के समर्थन में क्या बोले ब्रजेश पाठक?

छात्रों के प्रदर्शन को लेकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि जब आम लोग परेशानी में होते हैं तो सरकार उनकी मदद करती है और उनकी बात सुनती है। उन्होंने कहा कि वह उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और प्रभावित छात्रों के साथ खड़े हैं।

भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का इंतजार

UPSSSC की 4,612 जूनियर इंजीनियर भर्ती में शामिल अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि प्रक्रिया लंबे समय से आगे नहीं बढ़ने के कारण उनके सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों के मुताबिक, भर्ती में देरी का असर उनके करियर और भविष्य की योजनाओं पर पड़ रहा है। इसी वजह से वे सरकार और संबंधित विभाग से लंबित चरणों को जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं।

लखनऊ में जुटे अलग-अलग जिलों के अभ्यर्थी

अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचे। राजभवन कॉलोनी में उपमुख्यमंत्री के आवास के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं की ओर खींचा।

अभ्यर्थियों का कहना है कि उनका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया में बाधा डालना नहीं, बल्कि लंबे समय से लंबित मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। वे चाहते हैं कि संबंधित विभाग उनकी मांगों पर जल्द फैसला करे और भर्ती के अगले चरणों को स्पष्ट समयसीमा के साथ आगे बढ़ाया जाए।

नगर निगम की निर्माणाधीन परियोजनाओं की महापौर ने की समीक्षा, धीमे कार्यों पर ठेकेदार को फटकार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। महापौर सुषमा खर्कवाल ने बुधवार को लालबाग स्थित नगर निगम मुख्यालय में नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ बैठक कर निर्माण कार्यदायी संस्था सीएनडीएस द्वारा नगर निगम लखनऊ के लिए कराई जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण विकास एवं निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में महापौर ने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने निर्माणाधीन नगर निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया और मौके पर चल रहे निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया।बैठक में महापौर ने सीएनडीएस द्वारा कराई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, निर्माण की गति तथा कार्यों में आ रही बाधाओं के बारे में अधिकारियों और कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों से जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में निर्माण कार्य की गति धीमी है, उनमें तत्काल तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि नगर निगम की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी कार्य गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए निर्धारित समय के भीतर पूरे किए जाएं।समीक्षा बैठक में नगर निगम लखनऊ के नवीन मुख्यालय भवन के निर्माण, अमौसी में मैंगो पार्क, किला मोहम्मदी नाला के रीमॉडलिंग एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेन, आलमबाग से हैदर कैनाल तक गोतापल्ली नाले के डायवर्जन के लिए आरसीसी स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण तथा विभिन्न पंपिंग स्टेशनों पर बाढ़ पंपिंग एवं जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।इसके अलावा औरंगाबाद में वर्किंग वूमेन हॉस्टल, साहित्य पार्क तथा मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना 2025-26 के अंतर्गत जोन-7 में जोनल कार्यालय के निर्माण की स्थिति पर भी चर्चा की गई। महानगर क्षेत्र में कुकरैल नदी के किनारे अयोध्या मार्ग स्थित नगर निगम की भूमि पर प्रस्तावित अर्बन प्लाजा, डिजिटल लाइब्रेरी, बुक कैफे, फूड कोर्ट, रूफटॉप टैरेस रेस्टोरेंट, बेसमेंट पार्किंग सहित बहुउद्देशीय भवन और अन्य सुविधाओं के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई।बैठक के बाद महापौर सुषमा खर्कवाल ने नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ निर्माणाधीन नगर निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भवन के विभिन्न हिस्सों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और अधिकारियों से कार्यों की समयसीमा तथा गुणवत्ता के संबंध में जानकारी ली। निर्माण कार्यों में हो रहे विलंब पर महापौर ने नाराजगी जताई और संबंधित ठेकेदार को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।महापौर ने कहा कि नगर निगम मुख्यालय सहित सभी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शहर के विकास से सीधे जुड़ी हैं। इन परियोजनाओं को लंबित रखने से जनता को अपेक्षित सुविधाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता। इसलिए निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि कार्यों की लगातार निगरानी करें और किसी भी स्तर पर सामने आने वाली बाधाओं का तत्काल समाधान कराते हुए निर्माण कार्य आगे बढ़ाएं।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन परियोजनाओं का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता न हो।

चार थाना क्षेत्रों के पांच दबंगों पर कार्रवाई, छह माह के लिए जिला बदर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार थाना क्षेत्रों के पांच मनबढ़ एवं दबंग व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत गुंडा घोषित कर छह माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित कर दिया है। यह कार्रवाई संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ के न्यायालय द्वारा की गई है।पुलिस के अनुसार गोसाईगंज, कृष्णानगर, बंथरा और मोहनलालगंज थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों और लोक शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत न्यायालय में कार्रवाई की गई। सुनवाई के बाद संबंधित व्यक्तियों को गुंडा घोषित करते हुए छह-छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर किए गए लोगों में गोसाईगंज थाना क्षेत्र के सूरज मिश्रा (28 वर्ष), पुत्र लालजी मिश्रा, निवासी मातनटोला, चतुर्भुजी मंदिर के पास, कस्बा एवं थाना गोसाईगंज शामिल हैं।इसी क्रम में कृष्णानगर थाना क्षेत्र के सर्वेश पाल (21 वर्ष), पुत्र श्यामलाल पाल, निवासी 551क/480, संजय गांधी मार्ग, गली नंबर-4, आजादनगर तथा वीर सिंह (21 वर्ष), पुत्र राजकुमार यादव, निवासी अलीनगर सुनहरा को भी छह माह के लिए जिला बदर किया गया है।बंथरा थाना क्षेत्र के अंकित राज उर्फ अंकित गौतम (31 वर्ष), पुत्र दिलीप कुमार, निवासी ग्राम बंथरा सिकंदरपुर को भी छह माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित किया गया है।

संक्षेप

सावन महोत्सव में झूले का रॉड गिरने से दो नाबालिग बालिकाएं घायल, अस्पताल में उपचार जारी

लखनऊ। थाना गाजीपुर क्षेत्र में आयोजित सावन महोत्सव के दौरान झूले पर बैठी दो नाबालिग बालिकाएं झूले का रॉड ऊपर से गिरने के कारण घायल हो गईं। घटना की सूचना 18 अगस्त 2026 को करीब रात 8 बजे थाना गाजीपुर पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।प्रारंभिक जांच के अनुसार 16 वर्ष और 14 वर्ष की दोनों नाबालिग बालिकाएं अपनी सहेलियों के साथ सावन महोत्सव में आई थीं। इसी दौरान झूले का एक रॉड अचानक ऊपर से गिर गया, जिसकी चपेट में आने से नीचे बैठी दोनों बालिकाओं को चोटें आईं।घटना के बाद दोनों बालिकाओं को तत्काल उपचार के लिए सुषमा अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों के हाथ और पैर में चोटें आई हैं। दोनों बालिकाओं के परिजन मौके पर मौजूद हैं और उनका उपचार जारी है।पुलिस के अनुसार दोनों बालिकाओं की हालत सामान्य है। घटना के बाद मौके पर शांति एवं कानून-व्यवस्था कायम है। पुलिस द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच की जा रही है।

माल पुलिस ने गैर-जमानती वारंट में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार

लखनऊ। न्यायालयों द्वारा जारी गैर-जमानती वारंटों के अनुपालन में वांछित एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना माल पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार 19 अगस्त 2026 को थाना माल पुलिस की टीम क्षेत्र में भ्रमण, अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, शांति एवं कानून-व्यवस्था ड्यूटी तथा संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान वारंटी अपराधियों की तलाश के क्रम में पुलिस टीम ने संबंधित आरोपी के निवास स्थान पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के संबंध में जानकारी देते हुए नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों को भी नियमानुसार दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी की पूरी कार्रवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दिनेश पासी, पुत्र कल्लू पासी, निवासी ग्राम चक सैदापुर, थाना माल, लखनऊ, उम्र करीब 32 वर्ष के रूप में हुई है। उसका व्यवसाय मजदूरी बताया गया है।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 42 .09 लाख की साइबर ठगी, पुलिस ने 13 .83 लाख रुपये फ्रीज कराए

लखनऊ। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 42 .09 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में साइबर क्राइम थाना लखनऊ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की रकम में से 13 .83 लाख रुपये फ्रीज/होल्ड करा लिए हैं। पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों, मोबाइल नंबरों, इंटरनेट प्रोटोकॉल पते और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच तेज कर दी है। प्रारंभिक तकनीकी जांच में साइबर ठगी के तार कई राज्यों के साथ-साथ विदेशों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं।पुलिस के अनुसार जमील अब्बास जमाली ने साइबर क्राइम थाना लखनऊ में शिकायत दर्ज कराई थी कि साइबर ठगों ने उन्हें डिजिटल अरेस्ट किए जाने का भय दिखाकर कुल 42,09,869 रुपये की ठगी की। शिकायत के आधार पर थाना साइबर क्राइम में मुकदमा संख्या 89/2026, धारा 318(4), 319(2), 351(4) बीएनएस तथा 66डी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।विवेचना के दौरान सामने आया कि साइबर ठगों ने शिकायतकर्ता से ठगी गई रकम को कुल छह बैंक खातों में स्थानांतरित कराया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस टीम ने तत्काल संबंधित बैंकों से संपर्क कर खातों पर आवश्यक कार्रवाई कराई।

ज्वैलर्स की दुकान से सोने के आभूषण चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजनौर पुलिस ने ज्वैलर्स की दुकान में ग्राहक बनकर सोने के आभूषण चोरी करने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया।

पुलिस के अनुसार 17 मार्च 2025 को मानसरोवर सेक्टर-ओ, न्यू गुड़ौरा निवासी राजेश वाजपेयी ने थाना बिजनौर में तहरीर देकर बताया था कि उनकी दुकान पर एक अज्ञात महिला और दो अज्ञात पुरुष जेवर खरीदने के लिए आए थे। आरोपियों ने कुछ जेवर खरीदने के बाद मौका पाकर दुकान से कुछ अन्य जेवर चोरी कर लिए और वहां से फरार हो गए। तहरीर के आधार पर थाना बिजनौर में मुकदमा संख्या 79/2025, धारा 305(ए) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो विवेचना के दौरान रिंकी शुक्ला, ऋषि शुक्ला और शमी जोशी के नाम प्रकाश में आए। पुलिस के मुताबिक रिंकी शुक्ला और ऋषि शुक्ला को पूर्व में 29 मई 2025 को थाना तिलहर, जनपद शाहजहांपुर से संबंधित चोरी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। वहीं शमी जोशी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था। उसके विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय, लखनऊ के न्यायालय से गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।पुलिस टीम आरोपी की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। इसी दौरान 18 अगस्त 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी शमी जोशी को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे 19 अगस्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।पूछताछ में पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि 17 मार्च 2025 को वह अपने साथियों के साथ सोना खरीदने के बहाने महाकाल ज्वैलर्स की दुकान पर गया था। सभी लोग ग्राहक बनकर दुकान में पहुंचे और सोने के आभूषण खरीदने के संबंध में दुकानदार से बातचीत की। इसी दौरान कुछ सामान पैसे देकर खरीदने के बाद मौका पाकर उसके और उसके साथियों द्वारा दुकान से सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए।आरोपी के कथित बयान के अनुसार चोरी किए गए सोने के आभूषण लेकर वे लोग दुकान से निकल गए और रास्ते में चलते-फिरते लोगों को चोरी का सोना सस्ते दामों में बेच दिया। इससे प्राप्त रकम को आरोपियों ने आपस में बांट लिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके हिस्से में आई रकम उसने खर्च कर दी। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह काफी समय से इधर-उधर छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान शमी जोशी, पुत्र शिवकुमार, निवासी नयापुरवा, थाना बेनीगंज, जनपद हरदोई, उम्र करीब 30 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार इस गिरफ्तारी से थाना बिजनौर में दर्ज मुकदमा संख्या 79/2025, धारा 305(ए) बीएनएस से संबंधित वांछित आरोपी की गिरफ्तारी हुई है।यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ तरुण गाबा तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय के निर्देश पर, पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी रल्लापल्ली वसंथ कुमार के मार्गदर्शन और सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के पर्यवेक्षण में थाना बिजनौर के प्रभारी निरीक्षक कपिल गौतम द्वारा गठित टीम ने की।गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विजय सिंह, उपनिरीक्षक सुधीर कुमार और मुख्य आरक्षी अरुण कुमार सिंह थाना बिजनौर शामिल रहे।

'दिमागी नक्सली' यानी सियासी तापमान बढ़ाने वाले शब्द

लालकिले की प्राचीर से होने वाले प्रधानमंत्री के सालाना संबोधन पर चर्चाएं और बहसें होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री द्वारा प्रयुक्त दो शब्दों 'दिमागी नक्सल' ने चर्चाओं की तासीर बढ़ा दी है। ऐसा नहीं कि इन शब्दों के संजीदापन को प्रधानमंत्री नहीं जानते होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा इन शब्दों के प्रयोग के पीछे दो वजहे साफ नजर आती हैं। दरअसल इस बहाने प्रधानमंत्री देश के उस वर्ग की तरफ दिलाना चाहते हैं, जिसकी नजर में उनकी और उनकी सरकार का हर कदम गलत और दकियानूसी है। दूसरी वजह, अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को नए उत्साह से भरना है, जो हालिया कुछ घटनाओं से किंचित निराश हैं।

लालकिले की प्राचीर से देश के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उस पर एक बार फिर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, '21वीं सदी में यह बहुत ज़रूरी है कि हम दशकों पुरानी उन चुनौतियों को खत्म करें, जिन्होंने देश को पीछे रखा है। नक्सलवाद और माओवाद ने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने अनगिनत माताओं के युवा बेटों को छीन लिया और देश भर के परिवारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। लगभग चार दशकों तक, नक्सलवाद ने भारत के बड़े हिस्सों और उसकी आबादी के एक बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में रखा, बंदूक के दम पर शासन किया और संविधान की धज्जियां उड़ाईं। आज हथियारों वाले नक्सल से बड़ी चुनौती दिमागी नक्सली ज्यादा खतरनाक हैं, इससे देश को बचाना होगा।

कभी देश के एक तिहाई हिस्से को लाल गलियारे के रूप में जाना जाता था। कभी माओवादियों और नक्सलियों की समानांतर सत्ता नेपाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक समानांतर सत्ता चलती थी। उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों कों ' पशुपति से तिरूपति तक ' के नाम से जाना जाता था। देश का गृहमंत्रालय की कमान संभालने के बाद अमित शाह ने 31 मार्च तक देश को लाल गलियारे से मुक्त कराने का वादा किया था। अमित शाह की दोहरी रणनीति के चलते यह गलियारा अब नक्सली हिंसा और आतंक से मुक्त हो चुका है। इसे संयोग कहें या कुछ और, जिस वक्त लाल किले से प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त लाल गलियारे वाले उड़ीसा के मलकानगिरी और छत्तीसगढ़ के बस्तर के कई गांवों में पहली बार तिरंगा लहरा रहा था। उन तिरंगों को सलामी देने वालों में वे लोग भी भारतीय संविधान के तहत हासिल पुलिस या होमगार्ड की वर्दी में शामिल थे, जो हाल के दिनों तो इन इलाकों में भारतीय संविधान को नहीं मानते थे, जिनका मानना था कि सत्ता बारूद से निकलती है। अब भी उनके हाथों में बंदूकें हैं, जिनके ट्रिगर पर अब भी उनकी ही उंगलियां हैं,लेकिन अब वे भारतीय संविधान की मर्यादा से बंध चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बदलाव को रेखांकित किया है, लेकिन उन्हें आशंका है कि समाज के विशेषकर बौद्धिक वर्ग में जो नक्सलवादी मानस के लोग हैं, उनसे निबटना आसान नहीं है।

वैसे दिमागी नक्सली कोई नए शब्द नहीं है। करीब दशक भर पहले फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री ने इसी तरह अर्बन नक्सली शब्द का इस्तेमाल किया था। तब से वामपंथी हिंसा का विरोधी मानस इन शब्दों का खुलकर प्रयोग करता रहा है। वह मानता रहा है कि देश में जब भी अराजक परिस्थितियां बनती हैं, उसके पीछे अर्बन नक्सलियों की ही सोच काम करती है। कह सकते हैं कि दिमागी नक्सली शब्द ने उन्हीं शब्दों को नई पहचान दे दी है। देश का अधिसंख्य बौद्धिक समाज शायद ही इससे इत्तेफाक रखता हो, लेकिन अतीत में यह वर्ग 'दबाव समूह' के रूप में काम करता रहा है। छह अप्रैल 2020 को दंतेवाड़ा में घात लगाकर नक्सलियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 75 और छत्तीसगढ़ पुलिस के एक सवाल को बारूदी सुरंगों से उड़ा दिया था। इस घटना के बाद देश का बड़ा वर्ग सदमे में था। तत्कालीन मनमोहन सरकार ने नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए सैनिक कार्रवाई करने की ठान ली थी। उस दौरान भी दिमागी नक्सलियों को विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों में चिन्हित करने की प्रक्रिया चली थी। लेकिन शहरों में वामपंथी उग्रवाद के समर्थक लोगों के प्रबल विरोध के चलते मनमोहन सरकार सैनिक कार्रवाई से पीछे हट गयी थी। हालाकि इस घटना के तीन साल एक महीने बाद 25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में घात लगाकर नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तकरीबन समूचे नेतृत्व को उड़ा दिया था। भुक्तभोगी होने के बावजूद कांग्रेस की अगुआई वाली केंद्रीय सरकार ने नक्सलियों को नेस्तनाबूद करने के लिए न तो ठोस रणनीति बना सकी और न ही रोक लगाने में कामयाब हुई। वह सिर्फ 'रोकथाम' की रणनीति पर चलती रही, लेकिन अमित शाह ने इसे बदलकर 'पूरी तरह खत्म करने' की रणनीति को अपनाया। इसके तहत, 'वामपंथी उग्रवाद' के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति बनाई गई। देश को नक्सल मुक्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत संवाद, सुरक्षा और समन्वय पर जोर दिया। खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन किए जाने लगे। केंद्रीय और राज्य बलों के बीच बेहतर तालमेल बनाया गया और जरूरत के हिसाब से वित्तीय मदद के लिए खजाना खोला गया।

नागरिकों पर ही है शहर साफ रखने की जिम्मेदारी

इस यूनिट से 4650 लोगों को रोजगार मिलेगा। टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश-विदेश में नई पहचान दिलाने यह अहम कदम है।

विनीत नारायण

सिर्फ सरकार को कोसना काफी नहीं। हमें खुद को भी आईना दिखाना होगा। अवैध निर्माण, मानकों से ज्यादा मंजिलें, नालियों में कचरा फेंकना, ये सब हम खुद करते हैं। ग्रामीण जीवन में जो सामूहिक जिम्मेदारी की भावना थी, शहर आकर हम भूल गए। कहने को शहरी हैं, लेकिन व्यवहार जंगली जैसा।

बरसात शुरू होते ही शहरों की गलियों-मोहल्लों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। मौसम विभाग अगर सही अनुमान लगाता है तो मूसलाधार बारिश के अनुमान के बावजूद देश के हर शहर में बरसात के गंदे पानी के तालाबों के बीच नारकीय जिंदगी जीने को मजबूर क्यों हो जाते हैं? हर साल यही कहानी दोहराई जाती है। लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी क्या केवल सरकार की है? क्या नागरिकों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं? क्या कारण हैं कि हर साल मानसून में देश के कई शहर नदी नालों में तब्दील हो जाते हैं?

सरकार की बात करें तो इसके तीन बड़े कारण हैं। पहला, बिना योजना के बसी कॉलोनियाँ और प्रशासन की आँख मूँदकर दी गई अनुमति। सड़क, नाली, सीवरज कुछ भी सही न हो तो भी कॉलोनी पास। दूसरा, नालियों और सीवर में ठोस कचरा जमा होना, क्योंकि स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते। तीसरा और सबसे खतरनाक, हर दो-तीन साल में सड़कों की ऊँचाई बढ़ा देना। जिससे आसपास के मकानों का तल हमेशा नीचे होता जाता है और पानी भराव की मुख्य वजह बन जाता है।

पहले दो कारणों पर तो हर साल मीडिया में शोर मचता रहता है। लेकिन सड़क का बार-बार ऊँचा होना कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि जितनी मोटी सड़क बिछाई जाएगी, ठेकेदार और इंजीनियरों का मुनाफा उतना ही बढ़ेगा। पहली बार अच्छी गुणवत्ता की सड़क बना दी जाए तो बार-बार बनाने की जरूरत ही न पड़े। थोड़े-बहुत पैचवर्क से काम चल सकता है, वहाँ भी पूरी नई सड़क डाल दी जाती है। बिना इस बात का लिहाज किए कि सड़क के दोनों तरफ रहने वाले आम लोगों की इतनी हैसियत नहीं होती कि वे हर दो साल में अपने घर का फर्श ऊँचा करा लें।

यदि विदेशों से तुलना की जाए तो एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि विदेशों की किसी कॉलोनी की सड़क अचानक ऊँची हो गई हो या किसी मकान का फर्श सड़क से नीचे हो गया हो। सौ साल पुराने मकानों में भी यह समस्या नहीं है। न सड़क का स्तर बढ़ा, न घर का फर्श नीचा हुआ। तो हमारे इंजीनियरों की अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? या समझते तो हैं, लेकिन रिश्वत की हवस में करोड़ों लोगों की जिंदगी में हर दो-चार साल मुसीबत खड़ी कर देते हैं।

लेकिन सिर्फ सरकार को कोसना काफी नहीं। हमें खुद को भी आईना दिखाना होगा। अवैध निर्माण, मानकों से ज्यादा मंजिलें, नालियों में कचरा फेंकना, ये सब हम खुद करते हैं। ग्रामीण जीवन में जो सामूहिक जिम्मेदारी की भावना थी, शहर आकर हम भूल गए। कहने को शहरी हैं, लेकिन व्यवहार जंगली जैसा।

आजकल सोशल मीडिया पर कुछ रील्स वायरल हो रही हैं। उनमें आम नागरिक दिखते हैं जो हाथ में फावड़ा-झाड़ू लेकर सड़क पर खड़े हैं। ये लोग जल भराव वाली सड़कों पर नालियों से प्लास्टिक, पॉलीथीन, गंदगी निकालते हुए देखें जाते हैं। कोई सरकारी विभाग का इंतजार नहीं कर रहा। खुद अपना इलाका साफ कर रहे हैं ताकि बारिश का पानी रुक न जाए। ये छोटी-छोटी कोशिशें ही असल बदलाव ला सकती हैं।

ज़रूरत है तो संगठित होने की। हम संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछें। उनसे पूछें कि सड़क का स्तर हर दो साल में क्यों बढ़ाया जाता है। और अगर वे जवाब न दे पाएँ तो दबाव बनाएँ कि सड़क को उसके मूल स्तर पर लाया जाए।

आज जरूरत है कि हम उन वायरल रील्स वाले नागरिकों से सीखें। ज़रूरत पड़ने पर खुद निकलकर नालियाँ साफ करें, कचरा न फेंकें, और साथ मिलकर प्रशासन पर दबाव बनाएँ। समस्या तभी घटेगी, जब हम अपनी उदासीनता छोड़कर खुद आगे बढ़ेंगे।

सोचिए, अगर हर मोहल्ले में सिर्फ दस-बारह लोग नियमित रूप से नालियों की सफाई करें या सरकारी विभाग पर साफ़-सफ़ाई का दबाव बनाएं तो क्या होगा? पानी का बहाव खुला रहेगा, मच्छर कम पैदा होंगे, बीमारियाँ घटेंगी और सबसे बड़ा फायदा, घरों में पानी घुसने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। वायरल रील्स में जो लोग दिख रहे हैं, वे कोई सुपरहीरो नहीं हैं। वे सामान्य नौकरीपेशा, दुकानदार, छात्र हैं। उन्होंने सिर्फ यह तय किया कि इंतजार करने से बेहतर है खुद काम करना। यही रवैया हमें अपनाना होगा।

एक और महत्वपूर्ण बात। सड़क की ऊँचाई बढ़ाने की समस्या सिर्फ पानी भराव तक सीमित नहीं है। जब सड़क ऊँची हो जाती है तो घर के दरवाजे-खिड़कियाँ सड़क के स्तर से नीचे आ जाते हैं। इससे घर में नमी बढ़ती है, दीवारें गीली रहती हैं, बिजली के तार खतरे में पड़ जाते हैं और बच्चों-बुजुर्गों के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कई परिवारों को मजबूरन घर का फर्श ऊँचा करवाना पड़ता है, जिसमें लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। यह खर्च आम आदमी की जेब पर भारी पड़ता है, जबकि जिम्मेदार ठेकेदार और अधिकारी मजे से मुनाफा कमाते रहते हैं। सोशल मीडिया आज सबसे ताकतवर हथियार है। अपने इलाके की सड़क की ऊँचाई का फोटो-वीडियो लें, पुराने और नए स्तर की तुलना दिखाएँ, और पोस्ट करें। स्थानीय विधायक, पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों को टैग करें। जब सैकड़ों लोग एक साथ आवाज उठाएँगे तो प्रशासन को जवाब देना ही पड़ेगा। साथ ही, मोहल्ला स्तर पर सफाई अभियान शुरू करें। रविवार की सुबह दो घंटे निकालकर नालियाँ साफ करना कोई बड़ी बात नहीं। यह छोटी सी मेहनत साल भर की परेशानी बचा सकती है।

याद रखें, सरकार और प्रशासन तभी जागते हैं जब नागरिक जाग जाते हैं। अगर हम सिर्फ कोसते रहे और खुद कुछ न किया, तो अगले साल फिर वही पानी, वही गंदगी और वही शिकायतें होंगी। लेकिन अगर हमने उन वायरल रील्स वाले नागरिकों की तरह जिम्मेदारी संभाली, तो बदलाव जरूर आएगा। नाली साफ करना शर्म की बात नहीं, बल्कि गर्व की बात है। क्योंकि यही असली देशभक्ति है, अपने आसपास को साफ और सुरक्षित रखना। समय आ गया है कि हम सिर्फ शिकायत न करें, बल्कि समाधान का हिस्सा बनें।

व्यंग्य

नौकरी की मजबूरी

भारतीय नाविकों के सामने भी नौकरी की मजबूरी है, जिससे जहाज मालिकों का निर्देश मानने के लिए वे विवश बने हुए हैं। जबकि फारस की खाड़ी, लाल सागर, और काला सागर में जोखिम बढ़ता जा रहा है।

लाल सागर में यमन के पास भारतीय झंडे वाला एक व्यावसायिक जहाज डूब गया। राहत की बात है कि जहाज पर सवार 14 नाविकों को बचा लिया गया, जिनमें 13 भारतीय हैं। भारतीय जहाज एसएसवी फैज नूर ओलिया पर यमन के हुदैदा/ मोखा बंदरगाह के पास मिसाइल अथवा ड्रोन से हमला हुआ। हमला किसने किया, तुरंत यह मालूम नहीं हो सका, लेकिन यमन के पास इस जलमार्ग में जहाजों को अक्सर अंसारुल्लाह (हुती) विद्रोही निशाना बनाते रहे हैं। अंसारुल्लाह ने लाल सागर में मौजूद बाब-ए-मंदाब जल मार्ग को आम नौवहन के लिए बंद कर रखा है। इसके पहले खाड़ी में पांच महीनों से जारी युद्ध के दौरान होरमुज जलडमरूमध्य के आसपास जहाजों पर हुए हमलों में कम-से-कम 14 भारतीय नाविक मारे जा चुके हैं।

इस बीच पिछले महीने काला सागर से गुजरने का प्रयास भी भारतीय नाविकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। बीते 18 जुलाई और 19 जुलाई को दो हमलों में पांच भारतीय नाविक मारे गए। ये हमले यूक्रेन ने किए। ऐसे मामलों में भारत सरकार की प्रतिक्रिया ₹कड़ी निंदा₹ करने तक सीमित रही है। पिछले महीने यह खबर जरूर मीडिया में आई थी कि भारत सरकार ने शिपिंग कंपनियों को खतरनाक इलाकों में जाने वाले जहाजों में भारतीय नाविकों की ड्यूटी ना लगाने का निर्देश दिया है। ऐसे कथित निर्देश के औचित्य पर तभी कई सवाल उठे थे। बहरहाल, अब यह साफ हो चुका है कि अगर सचमुच वैसा कोई दिशा-निर्देश दिया गया था, तो वह बेअसर साबित हुआ है।

तमाम नाविकों की तरह भारतीय नाविकों के सामने भी नौकरी की मजबूरी है, जिससे जहाज मालिकों का निर्देश मानने के लिए वे विवश हैं। जबकि फारस की खाड़ी, लाल सागर, और काला सागर में जोखिम बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के युद्ध में अब सबसे बड़ा मसला होरमुज का ही रह गया है, जिस पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए ईरान अडिग है। उधर हूतियों और सऊदी अरब के बीच लड़ाई छिड़ने से लाल सागर में भी खतरा बढ़ा है। इन सबके बीच भारतीय नाविकों को कैसे बचाया जाए, यह सवाल रोज अधिक बड़ा होता चला गया है।

ब्लॉग

मोदी को पता भी कि लालकिले से क्या बोला?

श्रुति व्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताजा जुमला इतिहास में उनकी याद का शायद एक और शब्द हो। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति, भारतीय मानस की शब्दावली में एक विचित्र नया लेबल जोड़ा—दिमागी नक्सल।

मानती हूं, मेरे जैसे लोगों के लिए इस शब्द में एक खास तरह की गूंज है। भारत सके लोगों ने भी इसे पकड़ने में देर नहीं लगाई। चौबीस घंटों के भीतर ही सोशल मीडिया पर गर्व से खुद को 'दिमागी नक्सल कहने वाले लोग आ गए, रेडिट पर इसके लिए अलग फ्लेयर की मांग होने लगी, दिमागी जनता पार्टी बनाने के मजाक चलने लगे, जबकि पी. चिदंबरम ने सीधे घोषणा कर दी कि उन्हें दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व है।

दरअसल राजनीतिक गालियों की एक दिलचस्प आदत होती है—वे अपने रचयिता के हाथ से तुंरत निकल जाती हैं। फिर दिमागी होना कोई सबसे बुरा आरोप भी नहीं है। आखिर सर्वप्रथम दिमाग तो है! लेकिन मजाक को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए और पहले उस मंच को देखिए जहां से यह कहा गया। स्वतंत्रता दिवस साल का वह एक दिन है जब प्रधानमंत्री केवल किसी पार्टी या सरकार के मुखिया की तरह नहीं, बल्कि गणराज्य की आवाज़ की तरह बोलता है। लाल किला वह जगह है जहां भारत खुद को देखता है—अपनी यात्रा, अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी उम्मीदों को—और अपने लोगों से, और दुनिया से, यह कहता है कि वह अपने बारे में क्या मानता है।

यही वह मंच है जहां से प्रधानमंत्रियों ने ऐसे शब्द छोड़े हैं जो अपने भाषणों से बड़े हो गए। नेहरू ने एक युवा भारत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक राष्ट्र-निर्माण की भाषा दी। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया—जय जवान, जय किसान—सैनिक और किसान, दोनों गणराज्य के केंद्र में। अटल बिहारी वाजपेयी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ा—विज्ञान भी वहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह ने इसी प्राचीर से भारत के ₹ज्ञान अर्थव्यवस्था₹ में प्रवेश की बात की। कहा कि दुनिया में भारत की जगह ₹नए शोध और नई सोच₹ पर निर्भर करेगी।

इनमें कोई भी परिपूर्ण प्रधानमंत्री नहीं था, न उनके समय का भारत कोई परिपूर्ण भारत था। यह तर्क भी नहीं है। भारत ने हर रंग की सरकार में सेंसरशिप, असहिष्णुता और असहमति के दमन को देखा है। तर्क इससे कहीं संकरा और सटीक है—शब्दावली का। असल बात, उस खास मंच पर खड़े होकर कोई नेता राष्ट्रीय कल्पना में क्या रखता है? क्या बताता है? जवान, किसान, विज्ञान, ज्ञान, नई सोच—इनमें से हर शब्द ने किसी न किसी तरह राष्ट्रीय कल्पना का दायरा बढ़ाया। किसी नई भूमिका को सम्मान दिया, किसी नई क्षमता को विकसित करने का आग्रह किया, भारत क्या बन सकता है इसका एक और रूप सामने रखा।

'दिमागी नक्सल इसका उलटा करता है।

यह उस शब्दावली में कोई नया जोड़ नहीं है। यह उसमें से कुछ घटाता है। लालकिले की इस परंपरा में पहली बार दिलचस्प पात्र वह भारतीय नहीं है जिसे बनने के लिए हमें कहा जा रहा है, बल्कि वह भारतीय है जिसे पहचानने के लिए कहा जा रहा है। कोई ऐसा नहीं जिसे राष्ट्रीय कल्पना के भीतर लाया जाए, बल्कि कोई ऐसा जिसे उससे अलग किया जाए। और यह भारत के उसी मंच से कहा गया है जिसका अर्थ कम-से-कम उस सुबह सबके लिए बोलना होता है। दूसरा, इस वाक्यांश को किसी पक्षधर की तरह नहीं, एक देशभक्त की तरह देखिए, तो इसमें कुछ गहरे स्तर पर अदेशभक्तिपूर्ण लगेगा। मैं यह शब्द पूरी गंभीरता से इस्तेमाल कर रही हूं।

पिछले बारह वर्षों में ₹राष्ट्रविरोधी₹ जुमला भारतीय राजनीति के सबसे आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले आरोपों में रहा है। प्रदर्शनकारियों पर, छात्रों पर, पत्रकारों पर, शिक्षाविदों पर, कार्यकर्ताओं पर, राजनीतिक विरोधियों पर। लेकिन राष्ट्रीय भावना के अधिक खिलाफ और क्या हो सकता है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री यह संकेत दे कि देश अपने सोचने वाले लोगों से ही सावधान रहे? भारत को इससे अधिक छोटा क्या कर सकता है कि भारतीय दिमाग—जिसे हम दुनिया के सामने अपनी ताकत के रूप में पेश करते हैं—उसे राजनीतिक संदेह की श्रेणी में बदल दिया जाए? भारत एक ऐसा देश है जिसे आज भी ज्ञान-शक्ति के रूप में जाना और सम्मान दिया जाता है। सिलिकॉन वैली में भारतीय मूल के सीईओ हमें राष्ट्रीय उपलब्धि लगते हैं। कोई भारतीय वैज्ञानिक विदेश में सफलता हासिल करे तो हम गर्व करते हैं। कोई भारतीय गणितज्ञ सम्मानित हो, हमारे इंजीनियर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए निर्माण करें—हमें गर्व होता है। हम शून्य और आर्यभट्ट को याद करते हैं, नालंदा और तक्षशिला को भी। हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियां चाहिए, रिसर्च यूनिवर्सिटियां, पेटेंट, नोबेल पुरस्कार, स्टार्टअप चाहिए। खुद प्रधानमंत्री मोदी बार-बार भारत के युवाओं से कहते हैं—इनोवेट करो, डिसरप्ट करो, सपने देखो, बड़ा सोचो। और फिर आता है—दिमागी नक्सल। विरोधाभास मज़ेदार होता, यदि वह इतना कुछ उजागर न करता। भारतीय दिमाग आविष्कार करे तो उसका उत्सव मनाइए। वही दिमाग सवाल पूछे तो बात जटिल हो जाती है।

इसीलिए मैं बार-बार नक्सल से ज्यादा दिमाग पर लौटती हूं। राजनीतिक भाषा अंततः इतिहास का प्रमाण बन जाती है। वह आने वाली पीढ़ियों को केवल यह नहीं बताती कि किसी सरकार ने क्या किया, बल्कि यह भी कि उसने किस चीज़ की प्रशंसा की, उसने क्या कल्पना की और कई बार वह किससे डरती थी। और इसीलिए इस शब्द की परिभाषा का न होना महत्वपूर्ण है। आखिर दिमागी नक्सल है कौन? मोदी ने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नक्सली विचारधारा अपने दिमाग में रखते हैं, देश और युवाओं को गुमराह करने के मौके तलाशते हैं और उन्हें ₹पहचानकर अलग-थलग₹ किया जाना चाहिए। लेकिन यह श्रेणी शुरू कहां होती है और खत्म कहां, यह नहीं बताया गया। जब भाषा साधारण राजनीतिक गाली की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की हो, तो यह कोई छोटा सवाल नहीं है। और यह अस्पष्टता संयोग भी नहीं है। यही इस शब्द की राजनीतिक उपयोगिता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी ऐसे कई शब्द दिए हैं। लेकिन यहां फर्क है। अर्बन नक्सल में कम-से-कम भूगोल था। आंदोलनजीवी के लिए कम-से-कम कोई आंदोलन होना जरूरी था। टुकड़े-टुकड़े गैंग में, कल्पनाशील ढंग से ही सही, किसी गैंग के होने का संकेत था। दिमागी नक्सल में किसी सदस्यता कार्ड की जरूरत नहीं। यहां भूगोल दिमाग के भीतर है। कुछ ही घंटों में दिख भी गया कि यह इलाका कितना फैल सकता है। एक छोर पर भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ₹दिमागी नक्सल इकोसिस्टम की मानसिकता₹ दिखाई है—सबूत यह कि वे समारोह में मौजूद नहीं थे। दूसरे छोर पर एक भाजपा मंत्री की कहीं अधिक गंभीर व्याख्या टिप्पणी में घूमती रही—दिमागी नक्सल यानी माओवादी समर्थक, संविधान को भीतर से कमजोर करने वाला, अलगाववादी, ऐसा व्यक्ति जो अनुच्छेद 370 की वापसी चाहता हो या यहां तक कि उत्तर-पूर्व को भारत से उसके संकरे 'चिकन नेक गलियारे के रास्ते काट देना चाहता हो। दूसरे शब्दों में—देशद्रोह, मानसिकता के कपड़ों में। लेकिन दोनों अर्थ एक साथ सही नहीं हो सकते।

यदि किसी समारोह में अनुपस्थित रहना किसी व्यक्ति को उसी श्रेणी में डाल देता है जिसमें देश को दो हिस्सों में काटने की साजिश करने वाला व्यक्ति आता है, तो उस शब्द का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। और जो सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीरता से लेने का दावा करती है, उसे इस शब्दावली को इतनी लापरवाही से खर्च करने वालों में सबसे आख़िर में होना चाहिए। यदि दूसरा, अधिक गंभीर अर्थ ही असली दिमागी नक्सल है, तो साफ कहिए। देश को बताइए—कौन माओवादी हिंसा का समर्थन कर रहा है? कौन संविधान को नकार रहा है? कौन उत्तर-पूर्व को अलग करना चाहता है? और प्रमाण दीजिए। यह भ्रम मोदी सरकार को उसके आलोचकों से अधिक परेशान करना चाहिए। क्योंकि आज जो लोग सबसे असुविधाजनक सवाल पूछ रहे हैं, वे दिमागी नक्सल की इन दोनों परिभाषाओं में सहजता से फिट नहीं बैठते। इस गर्मी में लीक हुए परीक्षा-पत्रों और अटकी भर्तियों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों ने यही दिखाया। यह समझने के लिए नरेंद्र मोदी और भारत के बौद्धिक प्रतिष्ठान के पुराने रिश्ते को याद करना उपयोगी है। 2014 में दिल्ली आए मोदी एक प्रतिष्ठान को चुनौती दे रहे थे। और उस चुनौती में दम था। भारत का पुराना बौद्धिक अभिजात वर्ग कई बार बेहद छोटा, बंद और खुद से असाधारण रूप से प्रसन्न रहने वाला था। दिल्ली के अपने ड्रॉइंग रूम थे, विश्वविद्यालय थे, सांस्कृतिक संस्थान थे, पत्रकार, नौकरशाह और गेटकीपर थे। अंग्रेज़ी की धार को बुद्धिमत्ता समझ लिया जाता था, सत्ता के निकट होने को भारत की समझ। प्रांतीय व्यक्ति को संरक्षण की निगाह से देखा जाता था। भारतीय भाषाओं में कही बात को 'परिष्कृत माने जाने से पहले अक्सर अंग्रेज़ी अनुवाद की जरूरत पड़ती थी। मोदी ने उस दुनिया के खिलाफ जमा नाराज़गी को बहुत अच्छी तरह समझा, भुनाया। उन्हें उस क्लब में बुलाया नहीं गया, तो उन्होंने अपना क्लब बना लिया। और फिर जीते। बार-बार जीते। लेकिन सत्ता में बारह साल किसी बाहरी व्यक्ति के बने रहने के लिए लंबा समय होता है। नरेंद्र मोदी अब भारत के प्रतिष्ठान के दरवाजे पर खड़े होकर भीतर आने की मांग नहीं कर रहे हैं। अब वे स्वयं प्रतिष्ठान हैं। उनकी पार्टी ने देश की राजनीति को बदल दिया है। उनकी शब्दावली रोजमर्रा की भाषा में उतर चुकी है। उनकी योजनाओं ने करोड़ों बच्चों का बचपन आकार दिया है। और वे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। यह वह पीढ़ी है जिसका लगभग पूरा बचपन मोदी के भारत में बीता है—मन की बात, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत और अब विकसित भारत के बीच। उसे आकांक्षा का वादा मिला था। मेरिट का। टेक्नोलॉजी से चलने वाले ऐसे भारत का जहां पुराने संपर्क और नेटवर्क कम मायने रखेंगे। अब वह इतनी बड़ी हो चुकी है कि उस वादे को परख सके। यही हाल के छात्र आंदोलनों को राजनीतिक रूप से दिलचस्प बनाता है। उन्होंने यह नहीं दिखाया कि युवा किसी व्यवस्थित तरीके से वामपंथ या कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने यह दिखाया कि युवा भारतीय मोदी के राष्ट्रवाद से सहमत हो सकते हैं, शायद उनकी प्रशंसा भी करते हों, लेकिन लीक होते प्रश्नपत्रों, अटकी भर्तियों और लगातार वादे बने हुए रोजगार से उनका धैर्य जवाब दे चुका है।

उनकी शिकायत उस राजनीतिक शब्दावली से कहीं कम क्रांतिकारी है जो उनके आसपास उछाली जा रही है। वे बस चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था काम करे। मोदी पुराने प्रतिष्ठान से लड़ना जानते थे क्योंकि वे उसका नाम ले सकते थे। कांग्रेस, वामपंथ, लुटियंस दिल्ली, टुकड़े-टुकड़े गैंग, आंदोलनजीवी – हर एक के साथ कोई विचारधारा थी, कोई पता था, कोई परिचित चेहरा। जेन ज़ी को किसी लेबल से खारिज कर देना कहीं मुश्किल सवाल है। यह पीढ़ी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वादे की तुलना अनुभव से कर सके। और उसका सवाल यह नहीं है कि मोदी का भारत का विचार सही है या गलत।

रामपुर-सहारनपुर से दिल्ली तक... सपा नेता आजम खान के कई ठिकानों पर ईडी की रेड

आर्यावर्त संवाददाता

रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल ऑफिस ने आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी की यह कार्रवाई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाली रकम के कथित डायवर्जन की जांच के तहत की गई है।

ईडी की जांच में अब तक क्या सामने आया है?

आरोप है कि सरकारी ठेकों का फायदा उठाने वाले कुछ निजी ठेकेदारों के जरिए रकम को कथित तौर पर जौहर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी की ओर डायवर्ट कर, वहां इस्तेमाल किया गया। ईडी की जांच में सामने आया है कि कुछ ठेकेदारों और जौहर ट्रस्ट के बीच वित्तीय लेन-देन हुआ।

सरकारी ठेकों की रकम डायवर्ट करने का आरोप

एजेंसी को शक है कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से हासिल रकम को अलग-अलग माध्यमों से ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया। आरोप है कि इस रकम का इस्तेमाल ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी से जुड़ी संपत्तियों के निर्माण समेत दूसरे कार्यों में किया गया। जांच में कथित तौर पर बड़े डोनेशन और निर्माण कार्यों से जुड़े वित्तीय लेन-देन भी सामने आए हैं।

10 ठिकानों पर क्या तलाश रही है ईडी?

ईडी की टीम रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में 10 ठिकानों पर वित्तीय दस्तावेज, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य खंगाल रही है-। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी फंड को किस तरीके से डायवर्ट किया गया और बाद में उस रकम का इस्तेमाल कहां-कहां और कैसे किया गया।

ईडी इन आधारों पर कर रही है जांच

ईडी की यह कार्रवाई मामले में मनी ट्रेल की जांच का हिस्सा है। तलाशी के दौरान मिलने वाले दस्तावेज और डिजिटल सबूत आगे की जांच में अहम हो सकते हैं। एजेंसी यह भी जांच करेगी कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से हासिल रकम का कथित तौर पर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का पूरा नेटवर्क क्या था और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे।

घर के तीन सदस्यों ने किया आत्मदाह का प्रयास

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर में बुधवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने आत्मदाह का प्रयास किया। उन्होंने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए खुद पर डीजल डाल लिया। परिवार का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।यह घटना बदलापुर क्षेत्र के सरोखनपुर के रहने वाले परिवार के साथ हुई। पीड़ित संतरा देवी ने बताया कि उनके पड़ोसी उनकी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने गांव के सूबेदार पर अपनी जमीन पर बिना अनुमति के अवैध निर्माण का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि उनकी जमीन के दूसरे नंबर पर भी कब्जा कर लिया गया है। जब वे विरोध करते हैं, तो विपक्षी मारपीट और फौजदारी पर उतारू हो जाते हैं। परिवार ने खुद को गरीब और असहाय बताया, जबकि विपक्ष को दबंग किस्म का व्यक्ति बताया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने इससे पहले भी जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, चकबंदी अधिकारी और संपूर्ण समाधान दिवस पर कई बार शिकायत पत्र दिए हैं। हालांकि, उनकी शिकायत पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वे यह कदम उठाने को मजबूर हुए।पीड़ित परिवार ने 17 अगस्त को एक बार फिर जिलाधिकारी को पत्र देकर गुहार लगाई थी कि यदि उनकी फरियाद नहीं सुनी गई, तो वे तहसील परिसर में आत्मदाह करने को विवश हो जाएंगे।पुलिस ने परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजवाया है।

बदायूं में भीषण हादसा : गंगा एक्सप्रेसवे पर कुत्ता सामने आने से पलटी कार

आर्यावर्त संवाददाता

बदायूं। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर मंगलवार देर रात करीब तीन बजे किमी नंबर 175 के पास एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक समेत सात लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। एक घायल युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

कार चालक के मुताबिक अचानक कुत्ता सामने आने से हादसा हुआ है। मौके पर कुत्ता भी मरा पड़ा मिला। कार की स्थिति देखने से लग रहा है कि पलटने के दौरान कार ने कई पलटी खाई। इसके चलते कार चारों ओर से काफी क्षतिग्रस्त हुई है। माना जा रहा है कि कार की रफ्तार काफी तेज रही होगी।

पुलिस के अनुसार, अर्टिगा गाड़ी CH02AA4318 में चालक समेत नौ लोग सवार थे। सभी अलग-अलग परिवारों के बताए जा रहे हैं। ये कार रुपैडिया नेपाल से चंडीगढ़ जा रही थी। किमी नंबर 175 के पास अचानक सड़क पर कुत्ता आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार पलट गई।

ये लोग हुए हादसे का शिकार

हादसे में नेपाल के जिला डांग निवासी दीपना खात्री (32 वर्ष) पत्नी नेमबहादुर और विपना सुनमगर (32) पत्नी विशाल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक दीपक ओली (28), पुष्पा (40), ज्ञान बहादुर मल्ल (22), यादव पोडे (22), विनोद (2), सिमोन (10) और एक अज्ञात व्यक्ति घायल हुआ है।

सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जहां अज्ञात घायल ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों शवों को सीएचसी वजीरगंज में रखवाकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतका विपना सुनमगर के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। दुर्घटनाग्रस्त कार को एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में खड़ा करा दिया गया है।

दीवार गिरी, मलवे में दबकर मां बेटी की मौत

जौनपुर। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत राजापुर सहावें गांव में बुधवार दोपहर रिहायशी छप्पर की दीवार अचानक भरभराकर ढह गई। मलबे में दबने से मां-बेटी की मौत हो गई। हादसे के दौरान उनकी दूसरी बेटी कोमल ने भागकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। उक्त गांव निवासी बिंदु राजभर मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बुधवार दोपहर वह घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान मिट्टी की दीवार अचानक गिर पड़ी। इसकी चपेट में आने से उनकी पत्नी 46 वर्षीय ज्ञानती देवी और 12 वर्षीय पुत्री अंबिका मलबे में दब गईं। अंबिका गांव स्थित विद्यालय में कक्षा छह की छात्रा थी। दीवार गिरते समय उसकी बहन कोमल भी पास में मौजूद थी। हादसा होते ही कोमल भाग निकली, जिससे उसकी जान बच गई।दीवार गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने आनन-फानन मलबा हटाकर मां-बेटी को बाहर निकाला।

3 रुपये के विवाद में ली थी 13 साल के बच्चे की जान, मिट्टी का तेल डालकर जिन्दा जलाया था... 16 साल बाद महिला को उम्रकैद

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। कानपुर देहात में 16 साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने दोषी महिला को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला महज तीन रुपये के विवाद से जुड़ा था। बिस्कुट खरीदने गए 13 वर्षीय बच्चे पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का आरोप महिला पर लगा था। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। मंगलवार को एडीजे चतुर्थ की अदालत ने महिला को दोषी मानते हुए उम्रकैद और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामला अकबरपुर क्षेत्र के घारमपुर गांव का है, जो अब रनिया थाना क्षेत्र में आता है। 16 अगस्त 2010 को 13 वर्षीय संदीप पड़ोस में रहने वाली ममता की दुकान पर बिस्कुट लेने गया था। संदीप ने दुकानदार को पांच रुपये का नोट दिया और दो रुपये का बिस्कुट मांगा। तीन रुपये वापस मांगने पर ममता ने पैकेट की कीमत पांच रुपये बताई।

मृतक के चाचा ने कराई थी हत्या की रिपोर्ट दर्ज

इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान ममता ने संदीप पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। आग में बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। उसे इलाज के लिए हैलट अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद संदीप के चाचा ने ममता के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर विवेचना पूरी की और 20 सितंबर 2012 को अभियुक्ता के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया।

16 साल तक मामले की सुनवाई चली

इसके बाद करीब 16 साल तक मामले की सुनवाई चलती रही। मंगलवार को एडीजे चतुर्थ की अदालत ने ममता को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी महिला पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामले में पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल की ओर से लगातार प्रभावी पैरवी की गई। लंबे इंतजार के बाद आए फैसले से 13 साल के संदीप को इंसाफ मिलने से परिजनों के लिए बड़ी राहत बनी है।

कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। राष्ट्रीय गीत वन्दे मातम के कथित अपमान और अनादर के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष अभिनव सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस मशाल जुलूस और कैंडल मार्च में सैकड़ों युवाओं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।यह विरोध जुलूस टीडी कॉलेज से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए जेसीज चौराहे तक पहुंचा। जुलूस के दौरान कार्यकर्ता हाथों में जलती हुई मशालें और मोमबत्तियां लेकर चल रहे थे। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना विरोध प्रकट किया। रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि वन्दे मातरम् केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत माता की अराधना और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का मूल मंत्र है। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा लगातार राष्ट्रीय प्रतीकों और देशभक्ति का अनादर किया जा रहा है, जिसे देश का युवा किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जेसीज चौराहे पर पहुंचकर जुलूस एक सभा में परिवर्तित हुआ।

जैसे ही खाली किया, 2 घंटे बाद भरभराकर ढहा मकान, परिवार बोला- देवी मां के कहने पर निकले थे घर से बाहर

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाली और आस्था से भरी घटना सामने आई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगाली मोहाल में सोमवार देर रात बारिश के बाद करीब 90 साल पुराना चार मंजिला जर्जर मकान ताश के पत्तों की तरह भरभराकर ढह गया। हैरानी और राहत की बात यह रही कि इस बड़े हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। परिवार के सभी सदस्य हादसे से ठीक दो घंटे पहले ही मकान खाली करके सुरक्षित बाहर निकल गए थे। इतना ही नहीं, घर में पले कुत्ते, खरगोश और मलबे के बीच स्थापित 6 फीट ऊंची देवी मां की मूर्ति भी पूरी तरह सुरक्षित मिली।

बंगाली मोहाल निवासी वेद प्रकाश मिश्रा, जो पानी सप्लाई का काम करते हैं, ने बताया कि उनका चार मंजिला मकान करीब 80 से 90 साल पुराना था। मकान के निचले हिस्से में देवी दुर्गा का मंदिर स्थापित है, जहां परिवार के सदस्य कई पीढ़ियों से पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं। वर्तमान में परिवार की वृद्धा मीरा देवी मंदिर की देखभाल और पूजा करती हैं।

मां मीरा देवी ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे जब वह मंदिर में देवी मां को भोग लगा रही थीं, तब उन्हें अचानक ऐसा अहसास हुआ जैसे देवी मां उनसे कह रही हों कि तुरंत घर खाली कर दो, वरना कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। शाम का अहसास होने के बाद रात करीब 9 बजे बंदरों के कूदने से मकान का छज्जा नीचे गिर गया। इसके बाद परिवार ने बिना देर किए जरूरी सामान, पालतू कुत्ता और खरगोश लिया और रिश्तेदारों के घर चले गए।

रात 11 से सुबह 5 बजे तक ढहता रहा मकान, मूर्ति रही सुरक्षित

परिवार के जाने के बाद रात करीब 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच चार मंजिला जर्जर मकान का अगला हिस्सा धीरे-धीरे पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। मंगलवार सुबह जब पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, तो देखा कि करीब 6 फीट ऊंची दुर्गा माता की मूर्ति मलबे के बीच बिना किसी नुकसान के सुरक्षित खड़ी थी। बउवा मिश्रा और पूरे परिवार ने इसे माता रानी का चमत्कार और असीम कृपा माना है। सूचना मिलने पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से इलाके में बैरियर लगा दिए हैं और जर्जर हिस्से को पूरी तरह गिरवाने का काम शुरू कर दिया गया है।

बारिश में कच्ची दीवार ढही, मलबे में दबे 80 वर्षीय वृद्ध

उधर, कानपुर से सटे उन्नाव जिले के सफीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरभौला गांव में बारिश के कारण कमजोर हुई एक कच्ची दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। नाती आनंद ने बताया कि उनके नाना सेवकी (80) का अपने भतीजे तेजपाल और महेश के साथ मकान को लेकर कोर्ट में दीवानी मुकदमा चल रहा है, जिसके चलते दीवार का निर्माण नहीं हो सका था।

सोमवार को बारिश के कारण दीवार गिरने से 80 वर्षीय सेवकी मलबे के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिजनों ने उन्हें बाहर निकाला और सफीपुर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है।

स्कूल वाहनों पर सख्ती, 68 बसों की फिटनेस फेल

जौनपुर। जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए।जिलाधिकारी ने कहा कि सभी स्कूली वाहनों के दस्तावेज दुरुस्त होने चाहिए। जिन वाहनों के परमिट, फिटनेस या अन्य जरूरी प्रपत्र पूरे नहीं हैं, उनके विद्यालयों में नोटिस चस्पा की जाए। इसके बाद भी दस्तावेज दुरुस्त न कराने पर संबंधित विद्यालय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।स्कूल वाहन निगरानी पोर्टल की समीक्षा में जनपद के 68 स्कूली वाहनों की फिटनेस फेल पाई गई। जिलाधिकारी ने ऐसे वाहनों की फिटनेस तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।उन्होंने सभी स्कूली वाहन चालकों का चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य कराने को कहा।

आंखों को सामने मां को उठा ले गया तेंदुआ, गांव में पुलिस फोर्स... पीएसी की टुकड़ी भी तैनात

आर्यावर्त संवाददाता

मुरादाबाद। मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र स्थित बलिया गांव में तेंदुए के हमले से एक वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार दोपहर के समय अपने परिजनों के साथ खेत में चारा लेने गई महिला बिरमा देवी (उर्फ बीरा देवी) पर झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया। 20 लोगों के बीच से तेंदुआ महिला को ले गया। परिजनों के शोर मचाने और भाले-बल्लम लेकर दौड़ने पर तेंदुआ महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ, लेकिन तब तक गंभीर रूप से घायल महिला की जान जा चुकी थी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है।

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। तेंदुए के बढ़ते खौफ को देखते हुए गांव में पुलिस बल, क्विक रिस्पॉन्स टीम और PAC की टुकड़ी तैनात कर दी गई है। वन विभाग के साथ मिलकर ड्रोन कैमरों से इलाके की निगरानी की जा रही है और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे (केज) लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने मृतक महिला के परिजनों को दैवीय आपदा के तहत 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए चौपालें लगाई जा रही हैं और अकेले जंगल या खेतों की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी जा रही है।

घटना के समय मौजूद मृतक महिला के बेटे प्रेमचंद ने आपबीती बताते हुए कहा। "हम खेत से न्यार (चारा) लेने गए थे। लगभग 15-20 लोग चारा लेने गाड़ियों में एक साथ गए थे। न्यार काटने के बाद जब गड्डी बांध रहे थे। तभी महज एक मीटर की दूरी से तेंदुए ने हमारी मां पर हमला कर दिया है। हम तुरंत भाले-बल्लम लेकर उस पर झपटे। तब जाकर वह मां को छोड़कर भागा था।" प्रेमचंद ने वन विभाग की लापरवाही पर गुस्सा जताते हुए कहा कि शाम 6 बजे के बाद गांव में तेंदुए का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने बार-बार पिंजरे (खटके) लगाने की गुहार लगाई, लेकिन वन विभाग टालमटोल करता रहा है। अब ग्रामीणों के सामने मवेशियों के लिए चारा लाने का संकट खड़ा हो गया है और खौफ के कारण रात में नींद तक नहीं आ रही है।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा इंतजामों की जानकारी देते हुए एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया। "थाना ठाकुरद्वारा के बलिया गांव में करीब दोपहर 2:30 बजे एक महिला चारा काटने खेत गई थी। जहां तेंदुए के हमले में उनकी मौत हो गई है।शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ग्रामीणों में कुछ रोष था। लेकिन उनसे बातचीत कर स्थिति सामान्य कर ली गई है। एसपी देहात ने बताया कि वन विभाग के साथ समन्वय बनाकर पिंजरे लगवाए जा रहे हैं और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। गांव में सुरक्षा के लिहाज से PAC की प्लाटून, क्विक रिस्पॉन्स टीम और स्थानीय पुलिस फोर्स तैनात कर रात में गश्त बढ़ाई गई है। इसके अलावा ग्रामीणों को अकेले न निकलने और समूहों में रहने की हिदायत दी जा रही है।

प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से किया संवाद

क्षेत्रीय स्थिति और प्रशासनिक मदद की जानकारी देते हुए एडीएम संगीता गौतम ने कहा कि मृतक महिला बिरमा देवी के परिवार को दैवीय आपदा के तहत कुल 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलते ही उपलब्ध करा दी जाएगी। एडीएम ने स्पष्ट किया कि मुरादाबाद का यह क्षेत्र जिम कॉर्बेट से सटा है। बारिश और गन्ने के खेतों के कारण लेपर्ड बाहर आ रहे हैं। क्षेत्र में लगभग 20-25 तेंदुए होने का अनुमान है। जिनमें से हाल ही में 6 पकड़े गए हैं। प्रभावित इलाकों में 20 पिंजरे लगाए गए हैं और जल्द 10 और लगाए जाएंगे। प्रशासन चौपाल लगाकर लोगों से समूह में बाहर निकलने की अपील कर रहा है।

बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए कांवड़िया जत्था रवाना

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। रिमझिम फुहारों और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच तखागंज से कांवड़ियों का विशाल जत्था बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। भगवा वस्त्रों में सजे कांवड़ियों के उत्साह और भक्ति से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व सभी कांवड़ियों ने गंज स्थित मां काली मंदिर एवं कड़े धाम शीतला माता मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इसके बाद डीजे पर बज रहे मधुर भजनों और भोलेनाथ के जयकारों के बीच कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। कांवड़ियों का जत्था नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए इंदिरा चौक, बदलापुर पहुंचा। यहां से सभी श्रद्धालु श्रीकृष्णा नगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां से ट्रेन में सवार होकर बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए।यात्रा के दौरान "बोल बम" और "हर-हर महादेव" के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। रिमझिम बारिश के बावजूद कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ से सभी के सुख, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। गिरजेश निगम, शनि निगम, रमेश गुप्ता, अजय गुप्ता अंकित यादव, प्रदीप गुप्ता, सत्यम गुप्ता, छोटू निगम, हिमांशु, संतोष शर्मा रेनू निगम सहित बड़ी संख्या में कांवड़िए एवं श्रद्धालु मौजूद रहे।

भारत के गांवों तक पहुंच गया डायबिटीज, इस वक्त 9 करोड़ मरीज: 2050 तक 85.3 करोड़ मरीजों का अनुमान

भारत में करीब 9 करोड़ लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं

1990 में 2.6 करोड़ से बढ़कर संख्या 2016 में 6.5 करोड़ हुई

भारत में डायबिटीज का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। 20 से 79 साल की उम्र के करीब 9 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। डायबिटीज अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं।

आज डायबिटीज यानी मधुमेह सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारी नहीं रह गई है। बदलती जीवनशैली, शहरों में बढ़ती भागदौड़, कम शारीरिक मेहनत और खान-पान में बदलाव ने इसे एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बना दिया है। हाल ही में सामने आए, इंटरनेशनल आंकड़ों के मुताबिक, भारत में 20 से 79 साल की उम्र के करीब 9 करोड़ लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं। इस संख्या के साथ भारत दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। चीन में ऐसे लोगों की संख्या करीब 14.8 करोड़ और अमेरिका में लगभग 3.9 करोड़ है।

सबसे चिंता की बात सिर्फ मौजूदा संख्या नहीं है, बल्कि आगे का अनुमान है। 2024 में दुनिया में 20 से 79 साल की उम्र के 58.9 करोड़ वयस्क डायबिटीज से प्रभावित थे, यानी लगभग हर 9 वयस्क में से 1 को डायबिटीज थी। अगर मौजूदा रफ्तार बनी रही तो 2050 तक यह संख्या बढ़कर 85.3 करोड़ हो सकती है।

स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती

भारत जैसे देशों में बढ़ती आबादी, लोगों की औसत उम्र बढ़ना, तेजी से होता शहरीकरण और कम सक्रिय जीवनशैली इस बढ़ते बोझ की बड़ी वजहें मानी जा रही हैं। अध्ययन के मुताबिक चीन, भारत और अमेरिका में ही 2024 में करीब 27.7 करोड़ डायबिटीज मरीज थे, जो दुनिया के कुल मामलों का लगभग 47 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि डायबिटीज अब सिर्फ व्यक्तिगत बीमारी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती बन चुकी है।

भारत में संख्या कितनी तेजी से बढ़ी?

भारत में डायबिटीज का बढ़ता बोझ अचानक सामने नहीं आया है। इंडियाः हेल्थ ऑफ द नेशन्स स्टेट्स रिपोर्ट और इससे जुड़े ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज अध्ययन के मुताबिक, 1990 में भारत में डायबिटीज के करीब 2.6 करोड़ मामले थे, जो 2016 तक बढ़कर 6.5 करोड़ हो गए। यानी करीब 26 साल में मरीजों की संख्या ढाई गुना हो गई। इसी दौरान 20 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में डायबिटीज की हिस्सेदारी 5.5% से बढ़कर 7.7% हो गई।

रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2016 में सभी राज्यों में डायबिटीज का बोझ एक जैसा नहीं था। तमिलनाडु और केरल में इसकी दर सबसे ज्यादा रही, जबकि दिल्ली, पंजाब, गोवा और कर्नाटक भी ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल थे। हालांकि, सबसे अहम बात यह है कि 1990 से 2016 के बीच डायबिटीज की दर हर राज्य में बढ़ी, यानी यह अब किसी एक इलाके या राज्य की समस्या नहीं रह गई थी।

मरीजों की संख्या नहीं, मौत का बोझ भी बढ़ा

भारत के 1990-2016 के आंकड़ों में डायबिटीज से होने वाली मौतों की दर में भी बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी। अध्ययन के अनुसार, प्रति एक लाख आबादी पर डायबिटीज से होने वाली मृत्यु दर 1990 में करीब 10 थी, जो 2016 में बढ़कर 23.1 हो गई। यानी इसमें करीब 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016 में डायबिटीज से होने वाली कुल मौतों में 42.6 प्रतिशत मौतें 70 साल से कम उम्र के लोगों में हुईं। डायबिटीज को अक्सर ऐसी बीमारी माना जाता है जिसे दवा और खान-पान से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन, जब इसका समय पर पता न चले या ब्लड शुगर लंबे समय तक नियंत्रित न रहे, तो इसका असर शरीर के दूसरे अंगों पर पड़ सकता है।

वजन और जीवनशैली का बड़ा कनेक्शन

पुराने भारतीय आंकड़ों में ओवरवेट यानी अधिक वजन को डायबिटीज से जुड़े बोझ का सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक बताया गया था। 2016 में डायबिटीज से जुड़े DALYs यानी बीमारी के कारण स्वस्थ जीवन के खोए वर्षों में करीब 36 प्रतिशत हिस्से को अधिक वजन से जोड़ा गया। नए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में भी बढ़ते डायबिटीज बोझ के पीछे आबादी की उम्र बढ़ने, शहरीकरण, कम शारीरिक गतिविधि और खान-पान में बदलाव को महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। खास तौर पर शहरों में लंबे समय तक बैठकर काम करना और ज्यादा प्रोसेस्ड या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड भोजन लेना जोखिम बढ़ा सकता है।

गांवों तक भी पहुंचा डायबिटीज का असर

भारत में डायबिटीज अब सिर्फ बड़े शहरों की बीमारी नहीं रह गई है, बल्कि इसका असर गांवों तक भी पहुंच चुका है। आईसीएमआर के INDIAB अध्ययन में ग्रामीण आबादी में भी डायबिटीज के मामले सामने आए हैं। चार क्षेत्रों के आंकड़ों में ग्रामीण इलाकों में डायबिटीज की दर शहरों से कम जरूर थी, लेकिन कई लोगों में बीमारी पहली बार जांच के दौरान सामने आई। तमिलनाडु में ग्रामीण आबादी में डायबिटीज की कुल दर करीब 7.8% और महाराष्ट्र में 6.5% थी, जबकि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में यह करीब 3% दर्ज की गई।

इसका मतलब है कि गांवों में भी बदलती जीवनशैली, खान-पान, कम शारीरिक गतिविधि और बढ़ते वजन के साथ डायबिटीज का खतरा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि ग्रामीण इलाकों में नियमित स्वास्थ्य जांच की सुविधा और बीमारी की शुरुआती पहचान शहरों की तुलना में कमजोर हो सकती है, इसलिए कई लोगों को डायबिटीज होने की जानकारी काफी देर से मिलती है। ICMR के अनुसार उसके INDIAB अध्ययन ने देश के 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 1,13,106 लोगों के आंकड़े जुटाए और डायबिटीज की राष्ट्रीय तस्वीर सामने रखी।

बुजुर्गों में सबसे ज्यादा खतरा

नए अध्ययन के मुताबिक डायबिटीज की दर 75 से 79 साल की उम्र के लोगों में करीब 25 प्रतिशत तक पहुंचती है। अध्ययन में पुरुषों में महिलाओं की तुलना में और शहरी इलाकों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में डायबिटीज ज्यादा पाए जाने की बात भी सामने आई है। लेकिन समस्या का एक छिपा हुआ हिस्सा भी है, कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज है। ऐसे मामलों में बीमारी का पता देर से चलता है और तब तक दिल, किडनी या आंखों से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए नियमित जांच और शुरुआती पहचान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जागरूकता बढ़ाने पर भी है जोर

डायबिटीज से निपटने के लिए सरकार का जोर सिर्फ इलाज पर नहीं, बल्कि समय रहते बीमारी की पहचान और लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर भी है। सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डायबिटीज की जांच और इलाज की सुविधाएं दी जाती हैं। इसके साथ ही जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग, शुरुआती जांच और जरूरत पड़ने पर बड़े स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करने की व्यवस्था है। आशा और एएनएम जैसी स्वास्थ्यकर्मियों की मदद से लोगों को डायबिटीज के जोखिम, खान-पान और जीवनशैली में बदलाव के बारे में जागरूक किया जाता है। सरकार ने mDiabetes जैसी मोबाइल पहल भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य लोगों को बीमारी की जानकारी देने, इलाज नियमित रखने और स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

भारत में 9 करोड़ डायबिटीज मरीज

भारत में करीब 9 करोड़ वयस्क डायबिटीज से प्रभावित हैं।
भारत दुनिया में डायबिटीज मरीजों की संख्या में दूसरे स्थान पर है।
चीन में करीब 14.8 करोड़ और अमेरिका में 3.9 करोड़ मामले हैं।
2024 में दुनिया में 58.9 करोड़ वयस्क डायबिटीज से प्रभावित थे।
2050 तक वैश्विक संख्या 85.3 करोड़ पहुंचने का अनुमान है।
दुनिया के कुल मरीजों में चीन, भारत और अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 47% है।

दोपहर में की गई इन गलतियों कारण कम होने लगती है शरीर की ऊर्जा

दोपहर के समय ऊर्जा का स्तर अचानक गिरना एक आम समस्या है, जिसका कई लोगों को सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण हमारी दिनचर्या और खान-पान से जुड़ा होता है। अगर आप भी दोपहर में थकान और सुस्ती महसूस करते हैं तो यह लेख आपके लिए है। यहां हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुधारकर आप अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं और पूरे दिन सक्रिय रह सकते हैं।

भारी और मसालेदार भोजन करना

दोपहर के समय भारी और मसालेदार भोजन करने से पाचन तंत्र पर अधिक दबाव पड़ता है, जिससे नींद आती है। इससे बचने के लिए हल्का और पौष्टिक भोजन करें, जैसे सलाद, दही या फल।

इनसे आपको जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और ऊर्जा भी बनी रहेगी। इसके अलावा पानी पीते रहें, ताकि आपका शरीर नमी से भरा रहे और आप तरोताजा महसूस करें।

इस तरह आप दोपहर में सुस्ती और थकान से बच सकते हैं।

चाय-कॉफी का अधिक सेवन कर लेना

चाय या कॉफी का अधिक सेवन करने से आपको अस्थायी ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन यह लंबे समय तक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है।

इससे शरीर में जलन बढ़ती है और नींद भी प्रभावित होती है। बेहतर होगा कि आप दिनभर में सीमित मात्रा में ही इनका सेवन करें और इसके बजाय हर्बल चाय या नींबू पानी पिएं।

इससे आपका शरीर नमी से भरा रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

लगातार स्क्रीन इस्तेमाल करना

लैपटॉप या मोबाइल स्क्रीन पर लगातार काम करने से आंखों पर तनाव पड़ता है, जिससे सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

इससे नींद आने की समस्या खड़ी हो जाती है। इससे बचने के लिए हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करें या दूर देखें।

इसके अलावा स्क्रीन ब्रेक लेने के लिए उठकर थोड़ी देर टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे आपकी आंखें आराम करेंगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

पर्याप्त पानी न पीना

शरीर को नमी से भरा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से भी थकान होती है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर में नमी बनी रहे और ऊर्जा स्तर भी ठीक रहे।

इसके अलावा आप नारियल पानी या ताजे फलों का रस भी पी सकते हैं, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं।

इससे आपका शरीर नमी से भरा रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे।

कसरत न करना

काम करते समय बीच-बीच में हल्की-फुल्की कसरत करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे मांसपेशियों में खिंचाव आता है और रक्त संचार बेहतर होता है।

आप कुर्सी पर बैठकर गर्दन घुमा सकते हैं, हाथ-पैर खींच सकते हैं या कुछ मिनट टहल सकते हैं। इससे आपका मन भी तरोताजा रहेगा और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे।

इस तरह आप अपनी दिनचर्या में हल्की-फुल्की कसरत शामिल करके आसानी से अपनी ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं।

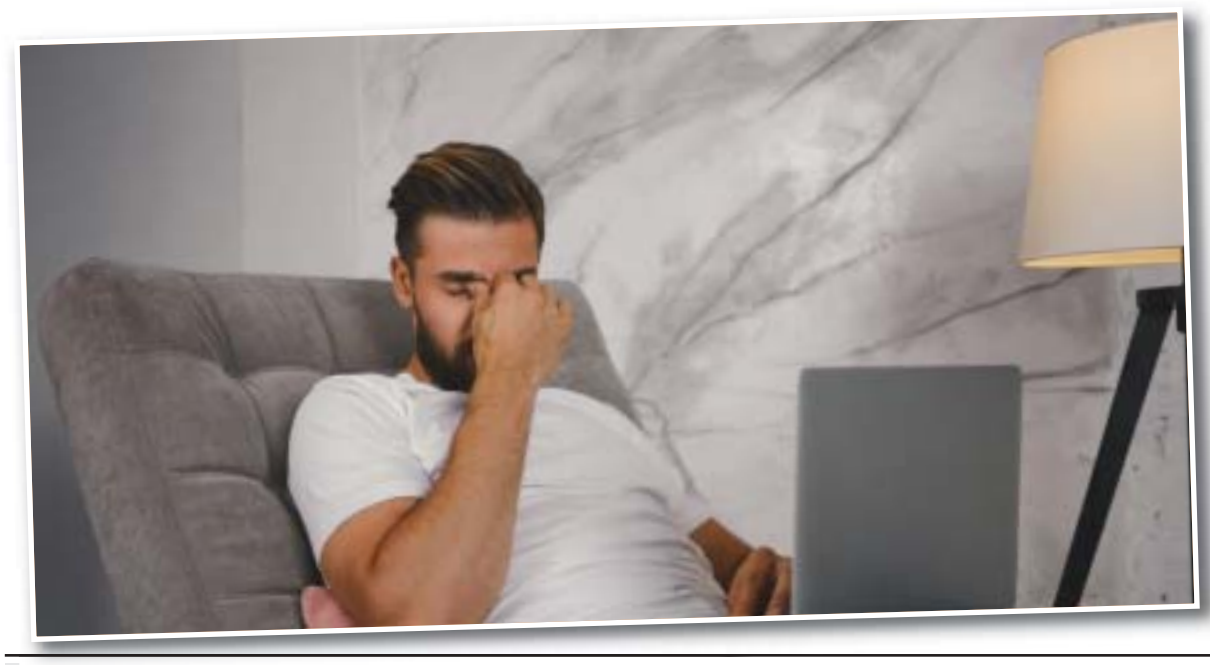

साइड लंज करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, मिलेगा संतुलन

साइड लंज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, जो आपके पैरों और कूल्हों को मजबूत बनाने में मदद करती है। यह न केवल मांसपेशियों को टोन करती है, बल्कि संतुलन और स्थिरता भी बढ़ाती है। हालांकि, साइड लंज करते समय कुछ सामान्य गलतियां हो सकती हैं, जिनसे चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिनसे आप साइड लंज करते समय संतुलन बना सकते हैं और चोट से बच सकते हैं।

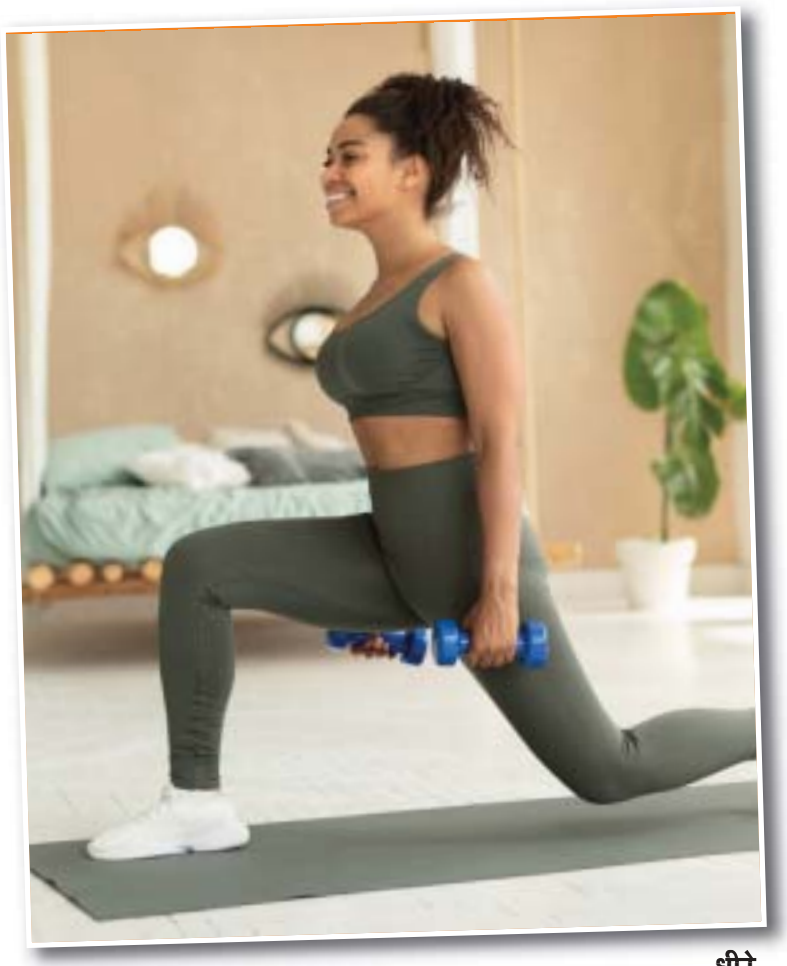

सही जूते पहनें

साइड लंज करते समय सही जूते पहनना बहुत जरूरी है। अच्छे पकड़ वाले जूते पहनें ताकि फिसलन न हो और पैर जमीन पर सही तरीके से टिक सकें।

सपाट सोल वाले जूते सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये जमीन पर बेहतर संपर्क बनाते हैं और फिसलने से बचाते हैं।

ऊंची एड़ी वाले जूते या चप्पल जैसे ढीले जूते न पहनें क्योंकि ये संतुलन बिगाड़ सकते हैं और चोट का कारण बन सकते हैं।

पैर फैलाने का तरीका सही रखें

साइड लंज करते समय पैर फैलाने का तरीका सही होना चाहिए। एक पैर को आगे और दूसरा पैर पीछे की ओर फैलाएं।

ध्यान रखें कि दोनों घुटने एक सीध में हों और पीछे वाला पैर पूरी तरह सीधा हो। इससे आपकी मांसपेशियां सही तरीके से काम करेंगी और चोट का खतरा कम होगा।

इसके अलावा इस स्थिति में शरीर का संतुलन भी बना रहता है, जिससे व्यायाम करना आसान हो जाता है।

शरीर का वजन सही तरीके से बांटे

साइड लंज करते समय शरीर का वजन सही तरीके से बांटना बहुत जरूरी है।

जब आप पीछे वाले पैर को मोड़ते हैं तो अपना वजन उस पैर पर डालें, जिससे आपको संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। इससे आपके घुटनों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा और चोट लगने का खतरा भी कम हो जाएगा।

इसके अलावा यह तरीका आपकी मांसपेशियों को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करेगा और आपको अधिक स्थिरता देगा।

हाथों की स्थिति पर ध्यान दें

हाथों की स्थिति भी साइड लंज करते समय अहम भूमिका निभाती है। अपने हाथों को कमर पर रखें या सामने फैलाएं ताकि आपको संतुलन बनाने में मदद मिले।

अगर आपके हाथ इधर-उधर घूमते रहें तो इससे संतुलन बिगड़ सकता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है।

इसके अलावा हाथों को सही स्थिति में रखने से आपके शरीर का केंद्र भी स्थिर रहता है, जिससे व्यायाम करना आसान हो जाता है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है।

धीरे-धीरे एक्सरसाइज करें

साइड लंज करते समय धीरे-धीरे गति बनाए रखना चाहिए। अचानक तेज गति से करने पर मांसपेशियां खींच सकती हैं या चोट लग सकती हैं।

इसलिए इसे धीरे-धीरे करें और हर कदम पर ध्यान दें। इससे न केवल आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, बल्कि चोट लगने का खतरा भी कम होगा।

नियमित अभ्यास से आप इस एक्सरसाइज में माहिर हो जाएंगे और इसके सभी लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इन सुझावों को अपनाकर आप साइड लंज करते समय संतुलन बना सकते हैं।

विदेशी निवेश पर नियम बदलेने की तैयारी में सरकार, 5,000 करोड़ की लिमिट बढ़ाकर 15,000 करोड़ करने का प्रस्ताव

विदेशी कंपनियों के लिए भारत में पैसा लगाना अब और आसान होने वाला है। सरकार विदेशी निवेश के पुराने नियमों को बदल रही है। इससे बड़े प्रोजेक्ट्स को फटाफट मंजूरी मिलेगी और व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा।

15 अगस्त 2026 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक 'विकसित भारत' का जो खाका खींचा था, उस पर सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। देश की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार विदेशी निवेश (FDI) के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, विदेशी पूंजी को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए बहुत जल्द कैबिनेट दो अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। पहला बड़ा बदलाव ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) के पास जाने वाले एफडीआई प्रपोजल की सीमा 5,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपये की जा सकती है। इसके अलावा, डाउनस्ट्रीम कंपनियों में विदेशी निवेश के नियमों को भी आसान बनाने पर विचार चल रहा है।

15 हजार करोड़ के विदेशी निवेश को डायरेक्ट मंजूरी

भारत में अभी तक का नियम यह है कि अगर कोई विदेशी कंपनी 5,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश करना चाहती है, तो उस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए सीधे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) के पास भेजना पड़ता है। यह व्यवस्था नवंबर 2015 से लागू है। 5,000 करोड़ रुपये से कम के निवेश प्रस्ताव संबंधित मंत्रालय खुद ही पास कर देते हैं। अब सरकार के नए प्रस्ताव के तहत इस सीमा को सीधा तीन गुना बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपये किया जा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब 15 हजार करोड़ रुपये तक के बड़े विदेशी निवेश प्रस्तावों को CCEA के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। संबंधित मंत्रालय अपने स्तर पर ही इन फाइलों को क्लियर कर सकेंगे। इससे सरकारी प्रक्रियाओं में लगने वाला समय काफी हद तक बचेगा और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जल्द शुरू हो सकेगा।

डाउनस्ट्रीम निवेश के नियमों में मिलेगी बड़ी राहत

सरकार सिर्फ निवेश की रकम की सीमा ही नहीं बढ़ा रही है, बल्कि उस कानूनी रास्ते को भी आसान बना रही है जिससे विदेशी पैसा भारतीय बाजार तक पहुंचता है। इसके लिए 'डाउनस्ट्रीम निवेश' यानी अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में बड़ी ढील दी जा सकती है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर मालिकाना हक वाली चेन (ओनरशिप चेन) में ऊपर मौजूद किसी घरेलू कंपनी ने पहले ही सरकार से विदेशी निवेश की जरूरी मंजूरी ले ली है, तो उसके नीचे काम करने वाली भारतीय कंपनी को दोबारा सरकारी इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। वर्तमान में दो खास स्थितियों में इस तरह की पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। पहला, जब निवेश ऐसे सेक्टर में हो जहां सरकार की अनुमति लेना जरूरी हो। दूसरा, जब पैसा भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की कंपनियों से आ रहा हो। नए नियमों से एक ही निवेश के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत खत्म हो जाएगी।

देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बूस्ट

बीते सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार काफी बड़ा हुआ है और इसके साथ ही निवेश की रकम भी कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में दशक भर पुराने नियम कई बार विकास की रफ्तार धीमी कर देते हैं। बार-बार मंजूरी लेने की लंबी प्रक्रिया से विदेशी कंपनियों का उत्साह भी कम होता है।खबरों की माने तो वित्त मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) और नीति आयोग के बीच इस मसले पर शुरुआती बातचीत पूरी हो चुकी है। अब बस कैबिनेट की हरी झंडी का इंतजार है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो देश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' यानी व्यापार करना काफी आसान हो जाएगा।

डीआरडीओ की नई तैयारी, सेना के लिए हथियार बनाने में अब प्राइवेट कंपनियां भी देंगी साथ

देश की सुरक्षा में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अब हमारी सेना को हथियार और मिसाइलें तेजी से मिलेंगी क्योंकि सरकारी एकाधिकार खत्म कर प्राइवेट कंपनियों को भी बम और मिसाइल बनाने का मौका दिया जा रहा है।

भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। अब तक जिन घातक रणनीतिक हथियारों और मिसाइलों का निर्माण केवल सरकारी कंपनियां करती थीं, उन्हें अब देश की प्राइवेट कंपनियां भी बनाएंगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने पहली बार मिसाइल और बम वेपन सिस्टम बनाने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। यह कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को नई गति देगा। ये फैसला देश की सीमाओं को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के आने से सेना को आधुनिक हथियार ज्यादा तेजी से और बड़ी मात्रा में मिल सकेंगे।

DRDO ने प्राइवेट कंपनियों से मांगे आवेदन

DRDO के मिसाइल एवं रणनीतिक सिस्टम विभाग ने भविष्य के अहम रक्षा प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) जारी किया है। इसके तहत अग्नि सीरीज जैसी मारक मिसाइलों से लेकर पनडुब्बी से लॉन्च होने वाले न्यूक्लियर हथियारों के नए वैरिएंट्स तैयार किए जाएंगे। मौजूदा समय में इन संवेदनशील हथियारों को बनाने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास है। नई योजना के तहत अब निजी क्षेत्र को भी इस अहम काम में साझीदार बनाया जा रहा है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) और सोलर एयरोस्पेस एंड डिफेंस जैसी स्थापित कंपनियों को इन बड़े प्रोजेक्ट्स में प्रमुखता से शामिल किए जाने की पूरी उम्मीद है।

रक्षा ठेके पाने की ये हैं सबसे अहम शर्तें

इस महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना किसी भी कंपनी के लिए आसान नहीं होगा। DRDO ने इसके लिए बेहद कड़े तकनीकी एवं वित्तीय मानक तय किए हैं। शॉर्टलिस्ट होने के लिए कंपनियों के पास रक्षा निर्माण का इंडस्ट्रियल लाइसेंस होना अनिवार्य है। इसके अलावा, विस्फोटकों के सुरक्षित रखरखाव के लिए पेसो (PESO) लाइसेंस भी होना चाहिए। वित्तीय योग्यता के तौर पर कंपनी का एक न्यूनतम टर्नओवर तय किया गया है। साथ ही, कंपनी की नेटवर्थ प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत के 5% से ज्यादा होनी चाहिए। केवल उन्हीं कंपनियों को तवज्जो दी जाएगी जिनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है।

भारी मात्रा में हथियार बनाने की क्षमता की होगी जांच

इस नई व्यवस्था को 'डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर' मॉडल के तहत लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत हर एक प्रोजेक्ट के लिए कम से कम दो कंपनियों का चयन होगा। ये चुनी गई कंपनियां शुरुआत में DRDO के साथ मिलकर टेस्टिंग के लिए हथियारों के प्रोटोटाइप तैयार करेंगी। जब इन हथियारों का सफल परीक्षण हो जाएगा, तब रणनीतिक बलों की मांग के आधार पर इन्हीं कंपनियों को बड़े स्तर पर उत्पादन का ऑर्डर मिलेगा।

सख्त निगरानी से तय होगी देश की सुरक्षा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि हथियारों की गुणवत्ता में कोई चूक न हो, DRDO 50 से 100 से अधिक हथियारों के थोक उत्पादन की क्षमता का कड़ाई से आकलन करेगा। इसके लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। यह समिति किसी भी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने से पहले उसकी फैक्ट्री का बारीकी से निरीक्षण करेगी। विशेषज्ञों की टीम खुद जाकर देखेगी कि कंपनी के पास जरूरी तकनीकी क्षमता, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया का सीधा अर्थ यह है कि भविष्य में भारत का रक्षा तंत्र और अधिक मजबूत होगा।

2020 चुनाव में 24 हजार गैर-नागरिकों ने डाला वोट, क्या जांच में और बढ़ेगा आंकड़ा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनगणना ब्यूरो 2020 के मतदाता आंकड़ों को नागरिकता संबंधी जानकारी से मिलाकर जांच कर रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि शुरुआती 12.8 करोड़ मतदाताओं की जांच में 24 हजार से ज्यादा गैर-नागरिकों ने अवैध तरीके से मतदान किया।

ट्रंप ने कहा, जनगणना ब्यूरो ने 2020 के मतदाता आंकड़ों को उनके नागरिकता रिकॉर्ड से मिलाकर जांच शुरू कर दी है। पहले 128,000,000 मतदाताओं की जांच में जनगणना ब्यूरो ने साबित किया है कि 24 हजार से ज्यादा गैर-नागरिकों ने अवैध रूप से वोट किया। जनगणना ब्यूरो अब अगले 3.2 करोड़ मतदाताओं का विश्लेषण करने जा रहा है और यह संख्या बहुत बढ़ जाएगी।

भारत की चुनाव प्रणाली की ट्रंप ने तारीफ की

इससे पहले ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते हुए कांग्रेस से सेव अमेरिका एक्ट पारित करने की अपनी मांग फिर दोहराई। ट्रुथ सोशल पर एक अन्य पोस्ट में ट्रंप ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हाल की बातचीत का जिक्र किया और भारत में मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र के इस्तेमाल की बात कही।

ट्रंप ने कहा, इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमारे प्रशासन से पूछा- अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना आप चुनाव कैसे करा सकते हैं? उन्होंने भारत में हुए सबसे हाल के आम चुनाव का भी जिक्र किया और कहा- भारत के पिछले चुनाव में 646,000,000 मतदाता थे। 1 प्रतिशत से भी कम लोगों ने डाक से मतदान किया और हर एक मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज होना जरूरी था।

व्हाइट हाउस ने नागरिकता की शर्त का समर्थन किया

व्हाइट हाउस के मुताबिक, प्रस्तावित कानून यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि संघीय चुनावों में केवल अमेरिकी नागरिक ही मतदान कर सकें। व्हाइट हाउस ने कहा, केवल अमेरिकी नागरिक ही अमेरिकी चुनावों का फैसला करें। व्हाइट हाउस ने इस विधेयक को 'समझदारी वाला, द्विदलीय विधेयक' बताया।

ट्रेड वॉर की कगार पर अमेरिका–कनाडा : ट्रंप की डेडलाइन से बढ़ी हलचल

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ विवाद को खत्म करने के लिए बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार दोपहर 12:01 बजे तक समझौता होने की समयसीमा तय की है। समझौता नहीं होने पर कनाडा से आने वाले करीब 20 अरब डॉलर के सामान पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है। इनमें हॉकी स्टिक, टंग डिप्रेशर समेत कई उत्पाद शामिल हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और ट्रंप पिछले दो दिनों में दो बार फोन पर बात कर चुके हैं। कार्नी ने बातचीत को 'गहन और नाजुक' बताया है और कहा है कि फिलहाल इसके बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं है। दोनों पक्ष आखिरी समय में किसी समझौते तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर विवाद नया नहीं है। दोनों देश सॉफ्टवुड लकड़ी, डेयरी बाजार और अन्य उत्पादों के व्यापार को लेकर लंबे समय से मतभेद रखते आए हैं। इसके बावजूद दोनों करीबी सहयोगी और महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बने हुए हैं।

सीमा पार कारोबार बेहद अहम

करीब 5,525 मील लंबी दोनों देशों की सीमा से रोजाना लगभग 3.3 लाख लोग और करीब 2 अरब डॉलर का सामान गुजरता है। कनाडा के कुल माल निर्यात का लगभग 72% अमेरिका जाता है। इसलिए किसी बड़े व्यापार युद्ध का असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता है।

ट्रंप का बदला हुआ रुख

ट्रंप का मौजूदा रुख पारंपरिक अमेरिकी-कनाडाई संबंधों से काफी अलग है। उन्होंने कनाडाई उत्पादों पर कई टैरिफ लगाए हैं और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने जैसी टिप्पणियां भी की हैं। इन नीतियों से कनाडा में अमेरिका के प्रति नाराजगी बढ़ी है और सरकार पर ट्रंप के सामने कड़ा रुख अपनाने का दबाव है।

अमेरिका की प्रमुख मांगें

मौजूदा बातचीत में अमेरिका चाहता है कि कनाडा ज्यादा अमेरिकी सैन्य उपकरण खरीदे, जिनमें F-35 लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। अमेरिका 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कनाडा की भागीदारी और महत्वपूर्ण खनिजों तक बेहतर पहुंच भी चाहता है। इसका उद्देश्य चीन से मिलने वाली रणनीतिक खनिज आपूर्ति पर अमेरिकी निर्भरता कम करना है।

ईरान के मिसाइल हमले के बाद यूएई का बड़ा फैसला, तेहरान से सभी व्यापारिक रिश्ते बंद

संयुक्त अरब अमीरात. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरान के साथ सभी व्यापार, कारोबारी लेनदेन और वित्तीय लेनदेन अगले आदेश तक रोक दिए हैं। UAE का यह फैसला ईरान से जुड़े एक नए मिसाइल विवाद के बाद आया है। इससे दोनों देशों के बीच हाल में सुधर रहे रिश्तों को बड़ा झटका लगा है। UAE के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, मंगलवार को उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाया। ये मिसाइलें UAE की तरफ आ रही थीं। इसके बाद UAE के लोगों के मोबाइल फोन पर कुछ समय के लिए मिसाइल खतरे का अलर्ट भेजा गया।

UAE का कहना है कि उसकी जांच में पता चला कि दोनों मिसाइलें समुद्री जहाजों को निशाना बनाने के लिए दागी गई थीं। एक मिसाइल UAE के क्षेत्रीय जल से बाहर समुद्र में गिरी, जबकि दूसरी UAE के क्षेत्रीय जल में गिरी। UAE के मुताबिक, इस घटना में कोई नुकसान या किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि, ईरान ने मिसाइल दागने से इनकार किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने UAE के आरोपों को बेबुनियाद बताया और क्षेत्र के देशों से ऐसे आरोप लगाने से बचने को कहा।

मिसाइल घटना के बाद UAE के विदेश मंत्रालय ने ईरान के खिलाफ बड़ा आर्थिक कदम उठाया। मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हमेली ने कहा कि क्षेत्र में बढ़ता तनाव शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। इसी वजह से ईरान के साथ सभी व्यापार, वाणिज्यिक आदान-प्रदान और वित्तीय लेनदेन रोक दिए गए हैं। यह रोक कब तक रहेगी, इसकी कोई तारीख नहीं बताई गई है।

यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ समय में UAE और ईरान के रिश्तों में धीरे-धीरे सुधार दिख रहा था। दोनों देशों के बीच कुछ व्यापारिक गतिविधियां फिर शुरू हुई थीं और कुछ ईरानी उड़ानें भी UAE लौटने लगी थीं। दुबई में कारोबार सामान्य होने लगा था। युद्ध शुरू होने के समय UAE से बाहर रह गए करीब 20 हजार ईरानी नागरिकों को भी वापस आने की अनुमति दी गई थी।

होर्मुज में पहले से बढ़ा हुआ तनाव

इस घटना का असर होर्मुज स्ट्रेट पर भी पड़ सकता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और LNG रास्तों में से एक है। युद्ध से पहले दुनिया के करीब पांचवें हिस्से का तेल और LNG इसी रास्ते से गुजरता था। लेकिन युद्ध और होर्मुज में जारी तनाव के कारण यहां जहाजों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। पिछले दिनों UAE ने ईरान पर अपनी सरकारी तेल कंपनी ADNOC से जुड़े जहाजों पर हमले का भी आरोप लगाया था। इन घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी।

मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सोने की खदान धंसी, हादसे में 30 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे

मध्य अफ्रीकी गणराज्य। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के पश्चिमी हिस्से में मंगलवार (18 अगस्त) को एक सोने की खदान अचानक धंस गई। इस हादसे में कम से कम 30 खनिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है, जिनकी तलाश की जा रही है। इस घटना से हड़कंप मच गया।

रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा नाना-माम्बेरे प्रांत के अब्बा इलाके में हुआ।अधिकारियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक, खदान में बचाव अभियान जारी रहा, हालांकि माना जा रहा है कि फंसे हुए लोगों के जीवित रहने की संभावना बहुत कम है।

फ्लोरियन गागुएंडे, जो इस हादसे में बचे खनिकों में से एक हैं, उन्होंने बताया कि नाना-मंबरे प्रांत के अब्बा क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक खदान अचानक से धंस गई। जिससे बड़ी संख्या में खनिक मलबे के नीचे दब गए। उन्होंने बताया कि बचावकर्मी अभी भी लोगों की तलाश कर रहे हैं, हालांकि, समय बीतने के साथ उनके जिंदा मिलने की संभावना कम होती जा रही है।

इधर अब्बा उप-प्रांत के उप महापौर सुलेमान बी ने बताया कि स्थानीय लोगों और बचाव दल ने कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद धंसी हुई खदान से 30 शव बाहर निकाले। उन्होंने बताया कि इस हादसे में घायल हुए कुछ खनिकों को अस्पताल में भर्ची कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने हादसे को बेहद भयावह बताया और संगठनों एवं आम लोगों से मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इधर इस हादसे के बाद सामने आए वीडियो में बचाव अभियान की भयावह तस्वीरें दिखाई दीं। फुटेज में चारों तरफ अफरा-तफरी मची नजर आ रही है।कीचड़ से सने ज्यादातर पुरुष और महिलाएं खनिकों को खदान से शव निकालते हुए देखाई दे रहे हैं। वहीं दर्जनों अन्य खनिक और मजदूर जख्मी हालत में पड़े हैं, जिनमें से कुछ मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इस बीच सरकार के प्रवक्ता एवरिस्त नगामाना ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को राहत और सहायता देने के लिए तेजी से काम कर रहा है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य में छोटी और पारंपरिक सोने की खदानों में हादसे आम हैं। यहां हजारों लोग छोटे स्तर पर खनन का काम करते हैं। पर्याप्त सुरक्षा उपकरण और आधुनिक सुविधाएं नहीं होने के कारण ऐसे खनन कार्य बेहद जोखिम भरे माने जाते हैं।

एनआरसी की मांग पर मणिपुर में सड़कें जाम: बंद से थमा घाटी का पहिया, सरकार ने किया मांग का समर्थन

इंफाल। मणिपुर में जनगणना से पहले नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) लागू करने की मांग को लेकर एक छात्र संगठन की ओर से बुलाई गई 48 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को घाटी के पांच जिलों में आम जनजीवन प्रभावित रहा। बाजार, शिक्षण संस्थान और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी ठप रहीं, हालांकि घाटी के कुछ इलाकों में निजी वाहन चलते नजर आए। हड़ताल का असर मुख्य रूप से घाटी के जिलों तक सीमित रहा, जबकि पहाड़ी जिलों में सामान्य गतिविधियां जारी रहीं।

इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट जिलों के अलग-अलग हिस्सों में हड़ताल समर्थकों ने बांस के खंभे और बड़े पत्थर रखकर सड़कें जाम

कर दीं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया और 'नो NRC, नो सेंसस' यानी 'NRC नहीं तो जनगणना नहीं' लिखे पोस्टर लगाए। घाटी के तीन अन्य जिलों—थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर—में भी हड़ताल का असर दिखाई दिया। यहां सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति कम रही, जबकि शिक्षण संस्थान बंद रहे।

पहाड़ी जिलों में नहीं दिखा बंद का असर

'कैंपेन फॉर जस्ट एंड फ्री डिलिमिटेशन' (JFD) की ओर से बुलाई गई इस राज्यव्यापी हड़ताल का पहाड़ी जिलों पर कोई खास असर नहीं पड़ा। चुराचांदपुर समेत पहाड़ी इलाकों में सामान्य गतिविधियां जारी रहीं। वहीं, मंगलवार को राज्य सरकार के प्रवक्ता और विधायक सपम रंजन सिंह ने कहा कि विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली जाकर केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेगा और उन्हें जनगणना से पहले NRC लागू करने की स्थानीय लोगों की मांग से अवगत कराएगा।

17 अगस्त से शुरू हुआ जनगणना का सेल्फ-एन्यूमरेशन चरण

जनगणना 2027 के तहत 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' यानी लोगों द्वारा खुद अपनी जानकारी दर्ज करने का चरण 17 अगस्त से शुरू होना था। इसके बाद मुख्य 'हाउस-लिस्टिंग' यानी घरों की सूची तैयार करने का काम 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। इसी समयसीमा को देखते हुए मणिपुर में NRC लागू करने की मांग तेज हो गई है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि राज्य में जनगणना से जुड़ी गतिविधियां शुरू होने से पहले NRC लागू किया जाए, ताकि अवैध प्रवासियों की पहचान की जा सके।

सेंसस कार्यालय के बाहर भी हुआ प्रदर्शन

NRC की मांग को लेकर छात्रों ने रविवार को इंफाल स्थित डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन्स के बाहर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इससे पहले 16 अगस्त की शाम इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट जिलों में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मशाल रैली निकाली थी। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि राज्य में जनगणना से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया शुरू होने से पहले NRC लागू किया जाए, जिससे अवैध प्रवासियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके।

सरकार ने NRC की मांग का किया समर्थन

मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार लंबे समय से NRC की मांग का समर्थन करती रही है। उन्होंने कहा, 'सरकार NRC की मांग का समर्थन करती रही है। विधानसभा ने भी पहले इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया है और केंद्र को इसकी जानकारी दी है।' मणिपुर विधानसभा ने 2022 में भी इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री ने हालांकि बंद और नाकेबंदी के बजाय विरोध का कोई दूसरा तरीका अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बंद और नाकेबंदी से दिहाड़ी मजदूरों और छात्रों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

भोपाल में 'जेन अल्फा' का हल्लाबोल! केवीएस में विलय के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे रीजनल स्कूल के छात्र

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 'जेन अल्फा' के छात्रों का एक अनोखा और उग्र विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। डेमोंस्ट्रेशन मल्टीपर्पस स्कूल (DMS), जिसे आमतौर पर रीजनल स्कूल के नाम से जाना जाता है, के छात्रों ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में अपने स्कूल के प्रस्तावित विलय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने स्कूल परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की और फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की।

छात्रों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, फैसले के खिलाफ नारे लगाए और चिंता जताई कि इस विलय से संस्थान का मूल उद्देश्य—शैक्षिक नवाचार और प्रयोग को बढ़ावा देना—कमजोर हो सकता है।

विरोध कर रहे छात्रों ने कहा कि डेमोंस्ट्रेशन मल्टीपर्पस स्कूल, जिन्हें रीजनल स्कूल भी कहा जाता है, दिसंबर 1965 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के तहत काम कर रहे हैं। ऐसे प्रायोगिक स्कूल चार शहरों—भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर—में स्थापित किए गए थे, जिनका उद्देश्य शिक्षण के नए तरीके विकसित करना और शिक्षा के नए तरीकों पर प्रयोग करना था।

स्कूल से जुड़े छात्रों और सदस्यों ने कहा कि वे इन संस्थानों को KVS में मिलाने के प्रस्ताव का विरोध करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि स्कूलों को एक अलग प्रशासनिक ढांचे के तहत लाने से उनकी खास पहचान और उन शैक्षणिक प्रयोगों पर असर पड़ सकता है, जिनके लिए उन्हें स्थापित किया गया था। विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारे लगाए और साफ कर दिया कि वे विलय को स्वीकार नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने रीजनल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर एस.के. गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियां और मांगें दर्ज कराईं। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि फैसले को वापस लिया जाए और प्रायोगिक स्कूलों की मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखा जाए।

अविका गौर ने फरहाना भट्ट से मांगी माफी, बोलीं-आप पर गुस्सा निकालना गलत था

अभिनेत्री अविका गौर इन दिनों रोहित शेट्टी के स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 को लेकर चर्चा में हैं। शो में खतरनाक स्टंट के साथ-साथ कंटेस्टेंट्स के बीच की दोस्ती, नोकझोंक और तनाव भी दर्शकों का ध्यान खींचता है। इसी बीच अविका और फरहाना भट्ट के बीच हुआ एक छोटा सा विवाद भी सामने आया, जिसमें अविका, फरहाना से नाराज नजर आईं। हालांकि, अब अविका ने खुद इस मामले पर सफाई दी है और माना है कि उस वक्त उनका व्यवहार सही नहीं था। उन्होंने फरहाना से सोशल मीडिया के जरिए माफी भी मांगी। दरअसल, शो में एक टास्क के दौरान अविका गौर फरहाना भट्ट की टीम में शामिल हुई थीं। टीम में आने के बाद फरहाना ने अविका का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई दी और अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। लेकिन उस वक्त अविका कुछ परेशान और नाराज दिखाई दे रही थीं। फरहाना के इस अंदाज का जवाब देते हुए अविका ने थोड़े रूखे अंदाज में कहा, आप तो चाहती नहीं थीं मैं आऊं।

इस घटना के बाद अब अविका गौर ने अपनी गलती स्वीकार की है। शो की शूटिंग पूरी होने और सभी कंटेस्टेंट्स के भारत लौटने के बाद अविका ने इंस्टाग्राम पर उस घटना का वीडियो शेयर किया। वीडियो के साथ उन्होंने फरहाना को टैग करते हुए लिखा, मुझे सच में अपना व्यवहार पसंद नहीं आया। फरहाना मुझे माफ कर दो। टीम को लेकर परेशान होकर मैंने आप पर अपना गुस्सा निकाल दिया, जो गलत था। आपको ढेर सारा प्यार।

अविका ने अपनी पोस्ट के अलावा कमेंट में भी फरहाना से माफी मांगी। उन्होंने लिखा, मुझे सच में अच्छा नहीं लगा कि मैंने ऐसा किया। सॉरी फरहाना। मुझे लगता है कि मैं बस परेशान थी और वह आपकी तरफ निकल गया। यह सही नहीं था। सॉरी स्वीटहार्ट।

बता दें कि खतरों के खिलाड़ी का यह 15वां सीजन है और इस बार शो में नए चेहरों के साथ कई पुराने कंटेस्टेंट्स की भी वापसी हुई। शो के इस सीजन की कास्ट में गौरव खन्ना, अविनाश मिश्रा, फरहाना भट्ट, शगुन शर्मा, अविका गौर, ओरहान अवत्रामानी (ओरी), हर्ष गुजराल, जैस्मिन भसीन, रुबीना दिलैक, करण वाही, ऋत्विक धनजानी, रुहानिका धवन और विशाल आदित्य सिंह शामिल हैं।

इंडस्ट्री में मैं जनता को खुश करने के लिए आई हूं, न कि किसी एक्टर को : काजल राघवानी

भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी इन दिनों रियलिटी शो भोजपुरी बवाल और अपने सोशल मीडिया बयानों के कारण चर्चा में हैं। अभिनेत्री ने सोमवार को फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ लोग उन्हें झूठा साबित करने पर तुले हुए हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री के 3 लोग उनका काम, टैग और हक छीनने में तुले हुए हैं। अभिनेत्री ने जारी किए गए नोट पर लिखा, सत्य हमेशा सत्य होता है और सत्य को झूठे लोग कुछ समय तक दबा जरूर सकते हैं, लेकिन सत्य को झूठ में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। मैंने जो कहा है सच कहा है और वो सब जानते हैं और जो अपने स्टारडम के दम पर इसे झुठलाना चाहते हैं, मुझे झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं 3 लोग मिलके तो सोचिए मेरी बात कितनी सच्ची होगी जिसे आप सब को मिलके झूठा साबित करने के लिए इस लेवल तक जाना पड़ रहा है।

अभिनेत्री ने अपना नोट शेयर करते हुए लिखा, बाप रे ये तो सब में बेस्ट है। लोगो में छीनने की आदत पड़ी है। चाहे काम हो, किसी का हक या फिर, किसी का टैग।

अभिनेत्री का कहना है कि वे अपने काम से जनता को अपनाने आई हैं, न की किसी एक्टर को। उन्होंने लिखा, इस इंडस्ट्री में मैं किसी एक्टर को खुश करने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि जनता का दिल जीतने के लिए आई हूं और वे ये सब देख ही रहे हैं।

अभिनेत्री दिनेश लाल यादव निरहुआ के द्वारा दिए बयान पर पलटवार करते हुए लिखा, एक कहते हैं कि पत्नी से प्यार नहीं है। जाहिर है क्योंकि उनकी पत्नी के साथ एक वीडियो वायरल हो गया था, तो सफाई भी देनी बनती है। एक प्रचार के लिए पत्नी को अपनाए और फिर छोड़ दिया। आज शो में कह रहे की एक लड़की भाव नहीं दे रही थी तो चार दिन बात नहीं की और फिर आई लव यू बुलवाया। फिर, जय श्री राम। वाह रे सरस्वती पुत्र की जय हो।

गौरतलब है कि अभिनेत्री का यह पोस्ट तब आया, जब भोजपुरी बवाल के हालिया एपिसोड में पवन सिंह, आम्रपाली और दिनेश लाल यादव निरहुला ने काजल राघवानी को घेरा था। हालांकि, शो में काजल राघवानी मौजूद नहीं थी।

काजल राघवानी का यह बवाल रियलिटी शो भोजपुरी बवाल पहले एपिसोड से ही देखने को मिला था, जिसमें अभिनेत्री ने अपने पुराने रिश्तों, शारीरिक शोषण, और इंडस्ट्री के अन्य कलाकारों (जैसे पवन सिंह, निरहुआ और आम्रपाली दुबे) पर कई गंभीर खुलासे किए थे, जिसके बाद भोजपुरी सिनेमा में भारी विवाद छिड़ गया है।

तमिलनाडु के उभरते गायकों को सामने लाएंगे ए. आर. रहमान, 18 अगस्त से शुरु तमिल आइडल के ऑडिशन

ए. आर. रहमान की आवाज और संगीत ने दुनियाभर के करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया है, लेकिन अब यही दिग्गज संगीतकार तमिलनाडु की उन नई आवाजों की तलाश में निकलने वाले हैं, जिन्हें अभी तक बड़ा मंच नहीं मिल पाया है। रहमान अब तमिल आइडल के जरिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों से उभरते गायकों को सामने लाने की तैयारी में हैं। शो के ऑडिशन 18 अगस्त से शुरू होंगे और इसके लिए तमिलनाडु के कोने-कोने से गायक आवेदन कर सकेंगे। तमिल आइडल की घोषणा सोनी विज्हा ने की है। इस शो के जरिए उन लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जो गायकी में आगे बढ़ना चाहते हैं। ए. आर. रहमान खुद इस तलाश का हिस्सा होंगे, इसलिए नए कलाकारों के लिए यह मौका काफी खास माना जा रहा है। शो का मकसद सिर्फ एक विजेता तलाशना नहीं, बल्कि तमिलनाडु के अलग-अलग हिस्सों से आने वाली ऐसी आवाजों को पहचानना है, जिनमें आगे चलकर बड़ा नाम बनने की क्षमता है। शो को लेकर ए. आर. रहमान ने कहा, नई आवाजों की तलाश संगीत की दुनिया का सबसे अहम हिस्सा है। जिन आवाजों को हम पहली बार सुनते हैं, उनमें से कई आगे चलकर लाखों लोगों तक पहुंचती हैं। इस सफर में नई प्रतिभाओं के साथ-साथ उनके अलग नजरिए और उनकी अनकही कहानियों को भी सामने लाने की कोशिश होगी। तमिल आइडल के जरिए पहली बार तमिलनाडु की बेहतरीन आवाजों को एक मंच पर लाया जाएगा, जहां उनके हुनर को पहचान और सम्मान मिल सके।

ऑडिशन 18 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। इच्छुक गायक सोनी लिव ऐप के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए हर किसी को किसी तय जगह पर पहुंचना जरूरी नहीं होगा। जो प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से ऑडिशन में शामिल नहीं हो सकते, वे अपने घर से भी इस प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।

इसके लिए प्रतिभागियों को सोनी लिव ऐप पर जाकर तमिल आइडल ऑडिशन वाले हिस्से को चुनना होगा। इसके बाद उन्हें अपनी जरूरी व्यक्तिगत जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इस बीच ए. आर. रहमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपने संगीत को लेकर लगातार सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने निर्देशक नायला अल खाजा की अरबी मनोवैज्ञानिक फैंटेसी-थ्रिलर फिल्म बाब के लिए संगीत तैयार किया है। यह रहमान का किसी अरबी फिल्म के लिए पहला सहयोग है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com